

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया : वह कामराज प्लान है, यमराज प्लान है, कौन सा है, इससे मुझे मतलब नहीं है। लेकिन यह जो यादवी फेल गई है उस यादवी की चर्चा विशेष रूप से न हों, दूसरे दलों की ओर लोग आकर्षित न हों यदि उसकी चर्चा की जाय, इसको रोकने के लिये, उनकी जवान पर ताले लगाने की दृष्टि से और इस खयाल से कि जो कांग्रेस की आपस की लड़ाई की वजह से व्यर्थ हो रहा है उसमें कोई और घुस नहीं आए, उस पर कलमबंदी के लिये, लेखनी पर प्रतिबंध लगाने के लिये, उसका विशेष उपयोग लिया जा रहा है। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, अगर हमारे कांग्रेस के सत्तारूढ़ दल के लोग आज भी इसके बारे में सिन्सियर हैं कि हमारे देश में संकट की स्थिति बनी रहनी चाहिये तो मैं उनसे ही प्रश्न करता हूँ : क्या वे कभी अपने दिल पर हाथ रख कर कहते हैं कि जितना संकटकाल के लिये हमें सन्नद्ध रहना चाहिये और उसके लिये हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिये और दैनिक जीवन में वैसा आचरण करना चाहिये, वैसा क्या हम कर रहे हैं ? वैसे तो यहां पर याजी जी अपनी जेप मिटाने के लिए संभवतः कह दें कि हम बराबर कर रहे हैं। मगर दिल से पूछें तो संकट की स्थिति हमें . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखियेगा।

#### ANNOUNCEMENT RE: GOVERNMENT BUSINESS

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SATYA NARAYAN SINHA): With your permission, Sir, I rise to announce that Government business in this House for the week commencing 9th March, 1964, will consist of;

1. Further consideration and return of the Appropriation (Rail-

ways) Bill, 1964, as passed by Lok Sabha.

2. Further consideration and passing of the Drugs and Cosmetics (Amendment) Bill, 1963, as reported by the Joint Committee of both Houses.
3. General Discussion on General Budget for 1964-65.
4. Consideration and return of the Appropriation Bills relating to the following: —

Demands on Account (General) for 1964-65.

Supplementary Demands for Grants (Railways) for 1963-64.

Supplementary Demands for Grants (General) for 1963-64.

As the above business is not likely to be completed by 13th March, I suggest, Sir, that the House may be pleased to sit on Monday, the 16th March, and Tuesday, the 17th March, if necessary.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M.P. BHARGAVA): The House stands adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one minute past one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock, the Deputy Chairman in the Chair.

#### RESOLUTION RE: ENDING STATE OF EMERGENCY—continued

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Chordia.

श्री विसलकुमार मन्नालालजी चौर-  
डिया : उपसभापति महोदय, मैं जो चर्चा  
कर रहा था उसमें इस बात पर प्रकाश डाल  
रहा था कि यह जो संकटकाल है तथा जो  
कांग्रेस में संकट उपस्थित हो गया है और  
उसको ठीक करने की दृष्टि से ही इस संकट  
को जारी रखना हमारी सरकार आवश्यक  
समझती है। यह स्वाभाविक है कि हमारे  
माननीय सदस्य चाहेंगे कि मैं इसके बारे में  
कुछ तथ्य रखूँ, तो मैं उनके सामने वर्तमान के  
कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ जिससे उनको  
इस बात की तसल्ली हो जायेगी कि कांग्रेस  
का संकट टालने के लिए ही यह कोशिश हो  
रही है। इसका सीधा अर्थ यह है कि इस  
संकट को जारी रखने से आप लेखनी पर प्रति-  
बन्ध लगाये रखना चाहते हैं, बोलने पर  
प्रतिबन्ध लगाये रखना चाहते हैं और जिस  
तरह से कृष्ण भगवान् के सामने यादवों की  
खींचातानी चल रही थी वैसे ही हमारे प्रान्तों  
में इस समय चल रही है और उसी को टालने  
के लिए इस इमरजेंसी को रखा जा रहा है।  
विरोधी दलों को भी दबाने के लिए आप इस  
इमरजेंसी के हथियार को अपने हाथ में  
रखना चाहते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना  
चाहूँगा कि क्या कारण है कि जब कन्नमवार  
महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री थे तो उस समय आचार्य  
अर्ते और नागपुर के दो पत्रकारों को डी०  
आई० आर० के अन्तर्गत गिरफ्तार कर लिया  
गया ? जब कन्नमवार गये और नये मुख्य  
मन्त्री आये तो उन्होंने इस खुशी में उन्हें छोड़  
दिया। या तो इन लोगों ने कोई गुनाह नहीं  
किया था या जिस तरह से पहले राजा महा-  
राजा जब गद्दी पर बैठते थे तो इस खुशी में वे  
कैदियों को छोड़ दिया करते थे, उसी तरह से  
महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री जी ने भी अपनी खुशी  
में इन लोगों को छोड़ दिया। आचार्य अर्ते  
जी और नागपुर के जो दो पत्रकारों को पहले  
गिरफ्तार किया गया था क्या उनको पहले  
गिरफ्तार करना जस्टीफाइड कहा जा सकता  
है और फिर बाद में छोड़ देना भी जस्टीफाइड  
है ? मैं इन दोनों बातों का जवाब चाहता हूँ ?

श्री एल० एन० मिश्र (बिहार) : दोनों  
बातें जस्टीफाइड हो सकती हैं।

श्री विसलकुमार मन्नालालजी चौर-  
डिया : क्योंकि आपकी इस समय ब्रूट मैजा-  
रिटी है इसलिए आप हर बात को जस्टी-  
फाइड कह सकते हैं। आपकी जो मैजारिटी है  
उसमें जब तक कमी नहीं होगी आप दिन को  
रात कह सकते हैं और रात को दिन कह सकते  
हैं और यह दोनों चीजें आपके लिए जस्टीफाइड  
हैं। मगर आपको अपना दिल टटोलना चाहिये  
और अपने से पूछना चाहिये कि ओवर नाइट ही  
एक आदमी जो पहले कानून की खिलाफत  
करने पर गिरफ्तार किया गया था उसे नये  
मुख्य मन्त्री के आते ही क्यों छोड़ दिया जाता  
है ? जब नये मन्त्री जी आये तो वे लोग जो  
पहले कानून विरोधी समझे जाते थे वे एक दम  
अच्छे बन जाते हैं ? इसलिए मैं प्रार्थना करूँगा  
कि जैसा आप बतलाते हैं कि हमारे देश में  
संकट है तो इस चीज को दृष्टि में रख कर  
सरकार को कार्य करना चाहिये। जो छोटे  
छोटे लोग या पत्रकार गिरफ्तार किये जाते हैं  
जो आपके लिटिल लिटिल नेहरू हैं, लिटिल  
लिलिटल लीडर हैं, वे स्थानीय अधिकारियों  
पर दबाव डालते हैं और इस तरह की गड़बड़  
करवाते हैं। इस तरह से इस कानून का दुरुप-  
योग किया जा रहा है। हमारे देश में कुछ  
ऐसे संकुचित मनोवृत्ति के लोग हैं जो अधि-  
कारियों से मिल कर अपना काम बनाने के  
लिए इस कानून का दुरुपयोग करवा रहे हैं।  
सतना में इस तरह के केसेज हुए हैं।

दिल्ली में जो गुड़ काण्ड हुआ है उसकी  
भी काफी चर्चा है मगर इस कानून का प्रयोग  
ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं किया जाता है  
क्योंकि वे लो सत्तारूढ़ दल से सम्बन्ध रखते  
हैं। हमारे देश में संकटकाल की घोषणा की  
गई है और फिर भी कलकत्ते में इस तरह  
का काण्ड हुआ तो आपका डी० आई० आर०  
कहाँ चला गया था ?

श्री सी० डी० पांडे : दो दिन में वहां सब चीज खत्म हो गई थी ।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरडिया : यह तो आप कलकत्ते वालों से पूछ सकते हैं जिनके ऊपर यह बात बीती । आज भी हमारे देश में पंचगायियों की कमी नहीं है, प्रो पाकिस्तानियों की कमी नहीं है, प्रो चाइनीज की कमी नहीं है । आप यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि संकटकाल की स्थिति को जारी रख कर आप डी० आई० आर० के अन्तर्गत लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं । आज जनता के ऊपर टैक्स का भार बहुत बढ़ गया है और सारे लोगों के दिमाग में यह बात है कि चीजों के दाम दिन पर दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं मगर आप संकटकाल की स्थिति को जारी रख कर उनकी जवान को बन्द कर देना चाहते हैं, उनकी लेखनी को बन्द कर देना चाहते हैं । हमारे जो सत्तारूढ़ दल के लोग हैं, मन्त्रिमण्डल के लोग हैं प्रमुख लोग हैं उनका व्यवहार संकटकाल की स्थिति की तरह नहीं लगता है । ऐसा लगता है कि इन लोगों के लिए कोई संकटकाल है ही नहीं । यह जो संकटकाल है वह जनता को दबाने के लिए ही है, उसको दबाने के लिए ही जारी रखा जा रहा है । अभी हमारे नन्दा जी ने अपना प्रवचन दिया तो क्या वे अपने सारे दल के लोगों को, अपने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों से कहेंगे कि वे संकटकाल की स्थिति को ध्यान में रख कर उसकी अनुभूति कर आचरण करें ? आज देश में सचमुच संकटकाल की स्थिति पहले से ज्यादा गम्भीर हो गई है । यह कहना कि हम पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गये हैं सिर्फ कह देने से नहीं हो सकते हैं । ऐसा मुझे लगता नहीं है कि देश में संकटकाल की स्थिति को ध्यान में रख कर काम किया जा रहा है अगर किया जाता तो आज हमारे यहां सैबोटेज के कार्य होते नहीं दीखते । नागपुर में आग लगी, कलकत्ते में हवाई जहाज हुगली नदी में नष्ट हो कर गिर पड़ा, परबों हो जम्मू काश्मीर

में एक हवाई जहाज गिर पड़ा जिसका अभी तक पता नहीं चला । इससे पहले एक और हवाई जहाज जम्मू काश्मीर में तार से टकरा कर गिर पड़ा । क्या ये सब चीजें संकटकाल की घोषणा से ली अनुभूति के अभाव का परिणाम नहीं हैं ? ऐसा लगता है कि हमारा शासन संकट काल की जो वास्तविक स्थिति है उसके अनुभूति नहीं कर रहा है । वह तो इस समय सारे प्रान्तों में अपने आपसी झगड़ों में ही पड़ा हुआ है । आज हमें इस बात का अहसास करना चाहिये कि देश में जो एयर क्रेन या दूसरी सैबाटेज की घटनाएँ हो रही हैं वे क्यों हो रही हैं और इनके पीछे किसका हाथ है ? हमें बीमारी की जड़ में जाना चाहिये सिर्फ बीमारी बीमारी कहने से काम नहीं चलेगा और न वह कम हो हो सकेगी । दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है और इस संकटकाल में भी हमें उसी तरह का आचरण करना चाहिये था मगर मुझे दुःख होता है कि शासक दल ने इसके अनुरूप कार्य नहीं किया । शासक दल ने देश में संकट की स्थिति की तो घोषणा कर दी मगर उसके अनुरूप उसने कोई कार्य नहीं किया । इसलिये मेरी इस सरकार से यह प्रार्थना है कि अगर वह सचमुच संकटकाल को महसूस करती है तो उसको अपना सारा आचरण उसके अनुरूप बनाना चाहिये । जनता को दबाने के लिये, किसी दल के लोगों को दबाने के लिये उस कानून का दुरुपयोग नहीं करना चाहिये । दूसरे दल के लोगों को गिरफ्तार करके आपका संकटकाल टलने वाला नहीं है, आपको इन लोगों को छोड़ देना चाहिये । इस समय जो स्थिति है वह संकट की स्थिति नहीं प्रकट करती है, यह तो कांग्रेस का अपना संकट है और उसी को छिपाने के लिये संकट की स्थिति को जारी रखा जा रहा है । हमारी सरकार को इस सारी बात पर विचार करना चाहिये ।

आज सारे राष्ट्र में संकट है, मैं इस बात को मानता हूँ और स्थिति पहले से भी गम्भीर

होती जा रही है। मैं यह भी मानता हूँ कि इसका कारण कांग्रेस की उपेक्षा की नीति है, तुष्टीकरण की नीति है, दब्युपन की नीति है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज सरकार की नीतियों के ही कारण देश में संकट की स्थिति बनी हुई है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूँगा कि वह इस चीज की जड़ पर जाये और उसको ठीक करे। इस तुष्टीकरण की नीति से काम चलने वाला नहीं है। हमारी जो शान्ति और तुष्टीकरण की नीति चलती आ रही है उसी से आज देश में संकट की स्थिति है और इससे काम चलने वाला नहीं है।

SHRI P. N. SAPRU (Uttar Pradesh): Why don't you make peace?

SHRI C. D. PANDE: With whom?

SHRI P. N. SAPRU: With China.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: With aggressor he wants peace.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चोरड़िया : तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस संकटकाल में आपको अपना आचरण, अपने इल का आचरण ठीक रखना चाहिये। इस समय प्रांतों में, वहाँ के शाहनशाहों में चीफ मिनिस्टर्स में जो गड़बड़ी चल रही है उनसे भी आप कहें कि संकटकाल की स्थिति को देखते हुए उसी आचरण से काम करें। (Interruption.) तारिक साहब भी खुश हो गये होंगे क्योंकि अब काश्मीर में उनकी अपनी सरकार बन गई है। अभी तक वे वहाँ की सरकार के खिलाफ बातें कहा करते थे लेकिन ओवरनाइट में सब कुछ बदल गया। जहाँ नया मंत्रिमंडल आया कि हमारे तारिक साहब अब काश्मीर के बारे में विशेष चर्चा नहीं करते हैं, नहीं तो पहले ऐसा था कि काश्मीर में यह गड़बड़ हो रही है, तो यह जो मनोवृत्ति है, इस मनोवृत्ति को हम ठीक नहीं समझते हैं। हम गलत को गलत कहेंगे, संकट की स्थिति को संकट मान कर चलेंगे,

खराब स्थिति होगी तो खराब मान कर चलेंगे और अच्छी स्थिति होगी तो अच्छी मान कर चलेंगे। अगर यह शासन संकट की स्थिति मानता है तो यह मेरा नम्र निवेदन है कि वह उसके अनुसार आचरण करे, खुद सरकार उसकी अनुभूति और चेतना भी उसकी अनुभूति करे। शासन ज्यादा अनुभूति करे तो ज्यादा अच्छा होगा। वरन् इस संकटकाल की स्थिति की घोषणा के परिणामस्वरूप जो कीमतें बढ़ रही हैं, जो जनता पर भार पड़ रहा है, उससे एक व्यर्थ का टेंशन लोगों के दिमाग में बढ़ रहा है और अराजकता की भावना पैदा हो रही है। इसलिये या तो आप स्वयं अपना आचरण सुधारें या इस संकटकाल की स्थिति से मुक्ति ले करके भगवान का नाम लें या रघुपति राघव राजा राम जप करके संतोष करें। आधे मन से या दुतरफा सोचने से काम चलने वाला नहीं है। यही निवेदन है।

شری اے۔ ایم۔ طارق (جموں اور

کشمیر): مہذب قہتی چہر مہن -  
جہاں تک اس دہزولہشیں کا تعلق ہے  
مہن اس کی مٹلنت کرتا ہوں -

श्री प्रकाश नारायण सप्रू : पूरी मूखालि-  
फत तो नहीं करेंगे ?

شری اے۔ ایم۔ طارق : ادھی

کروں گا لہکنی جہاں تک اس چہر کا  
تعلق ہے جتلم نظر بند مہن اس  
ملک مہن اور کافی مہر سے مہن ان  
کو چہر دینا چاہئے - اگر وہ چہرے  
نہیں جاسکتے مہن تو ان کے خلاف  
چ شکایتیں مہن ان کو عدالت مہن  
لانا چاہئے - اس سے ایک صورت یہ  
پیدا ہو جائے گی کہ ملک کے جو

[ شری اے - ایم - طارق ]  
 چلند لوگ یا چلند جماعتیں قہفلس  
 آف انڈیا رولز کی مخالفت صرف اس  
 لئے کرتی ہیں کہ اس موجودہ سرکار  
 نے اسے لاکو کیا ہے ان کو لوگوں میں  
 یہ غلط بات بولنے کا موقعہ نہیں  
 ملے گا کہ قہفلس آف انڈیا رولز  
 موجودہ حکومت نے صرف اپنے سیاسی  
 فائدہ کے لئے لاکو کئے - بلکہ ان کو  
 یہ یقین ہو جائے گا اور ہمیں عوام  
 کو بھی یہ بتانا ہے کہ قہفلس آف  
 انڈیا رولز کی ضرورت اس ملک میں  
 ہے ، تو اور آگے بھی کچھ مدت کے  
 لئے رہے گی - ایمرجنسی کے معنی  
 یہ نہیں ہیں کہ ہمارے ملک میں  
 جنگ ہو تب ایمرجنسی پیدا ہوتی  
 ہے - ایمرجنسی اس وقت بھی پیدا  
 ہوتی ہے جب ملک کی سرحدوں کو  
 خطرہ ہو یا ملک کے اندر کچھ غم  
 ملے لوگ ملک کے ریلے والوں کی  
 مدد سے انفرانٹری بھیلاتے ہیں -  
 سازشیں کرتے ہوں اور ملک کے ریل و  
 رسائل اور خوراک کے پہنچانے کے  
 انتظامات میں یا دوسری چیزوں کو  
 جن کا عوامی زندگی پر اثر پڑتا ہو  
 روکنا بھی ایمرجنسی ہے - کچھ نہیں  
 تو اس ماحول کو قائم رکھنا نہایت  
 ضروری ہے - میں ان دوستوں کے ساتھ  
 اتفاق نہیں کر سکتا جو یہ کہتے ہیں کہ  
 ملک میں ایمرجنسی نہ ہو - چھٹی  
 حملہ سے پہلے بھی اس ملک میں  
 ایمرجنسی تھی اور چوبیس حملہ کے بعد  
 تو ایمرجنسی کی بے حد ضرورت ہے -

اس وقت ہمارے سامنے کوئی ایسی  
 ضمانت نہیں ہے کہ چین اور پاکستان  
 الگ الگ یا مل کر ہماری سرحدوں  
 پر حملہ نہیں کریں گے اگر آج ہندوستان  
 کو یہ ضمانت مل جائے کہ پاکستانی  
 اور چین ہندوستان کے علاقوں پر حملہ  
 نہیں کریں گے اور پاکستان کے لوگ  
 ہندوستان کی سرحدوں کے اندر گزرو  
 کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو  
 ایمرجنسی بذات خود ختم ہو جائیگی  
 لہذا ان دونوں چیزوں کی ہمارے  
 پاس کوئی ضمانت نہیں ہے بلکہ اگر  
 ہم ضمانت دارانہ طور ایک ہندوستانی  
 کی حیثیت سے یہ چھوڑ کر کہ ہم  
 کسی ضمانت کے اندر ہیں اس بات  
 کو دیکھیں تو ہم کو یہ یقین  
 ہو جاتا ہے کہ اس ملک میں  
 ایمرجنسی ہے -

میں مستر بھوپنڈھ کیپٹا کی  
 مخالفت اس لئے نہیں کر رہا ہوں  
 کہ وہ مختلف جماعت کے ممبر ہوں  
 یا لیڈر ہیں اور انہوں نے یہ ریپولیشن  
 پیش کیا ہے بلکہ میں نے اکثر  
 موقعوں پر ان کی حمایت کی ہے  
 اور مودے دوست آئریبل پانڈے یہ  
 سمجھتے ہیں کہ میں ان کا زیادہ  
 ساتھی ہوں اور پانڈے صاحب کا کم  
 ہوں - لہذا حقیقت یہ ہے کہ  
 جب ملک کا معاملہ سامنے ہو تو  
 اس میں انفرادی دوستی کے معنی  
 کچھ نہیں رہتے - ملک کی اہمیت

روپے لاکھ لکھے گئے ہیں اور یہ اس لئے لاکھ لکھے گئے ہیں کہ ملک میں خوداک کی قیمتیں نہ بڑھیں اور ملک میں رسل و رسائل کو نقصان نہ پہنچے۔ اور ملک میں مذہب کے نام پر فسادات نہ کرائے جائیں۔

श्री प्रकाश नारायण सक्लू : ये सब चीजें हो रही हैं ।

شری اے - اہم - طارق : یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اس میں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن حکومت کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جن چیزوں کو روکنے کے لئے اس کو لاکھ لکھا گیا تھا ان کے روکنے میں اس کا صحیح حد تک استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ بد قسمتی سے کئی ہزار سال پرانا ہے اور ہر وقت ہم اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارا کلچر ایک شرافت کا ہے، بزرگی کا ہے اور رواداری کا ہے اور تینوں چیزوں میں ہم مارے جاتے ہیں۔

एक मानवीय सदस्य : कौन कौन चीजें ?

شری اے - اہم - طارق : بزرگی، شرافت اور رواداری اور اس کی مثال میں خود کھڑا ہیں۔ تو ان تینوں چیزوں سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا

کے خیال سے آپ پچھلے دو مہینوں میں دیانت داری سے دیکھیں کہ کشمیر کے اندر کتنے ایسے کھسکے ہوئے ہیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اس ملک میں ایمرجنسی کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی سازشوں کے خلاف ہمارے جن کی سازشوں کے خلاف ہی ایمرجنسی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس لئے بھی ایمرجنسی کی ضرورت ہے کہ اس ملک میں کچھ لوگ مذہب کے نام پر ذات پات کے نام پر سوشلزم اور سرمایہ داری کے نام پر اندرونی گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں دلی میں اسٹرائیکیں ہو رہی ہیں، بڑے بڑے کارخانوں میں اسٹرائیکیں ہو رہی ہیں تو آج اس ملک کو اس وقت جنگی حالات کا سامنا ہے۔ ہماری سرحدوں پر ایک طرف ہماری فوجیں ہیں اور دوسری طرف چھٹی فوجیں ہیں اور ایک طرف ہماری فوجیں ہیں دوسری طرف پاکستانی فوجیں اور حالات ایسے ہیں کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ کس وقت کیا ہو جائے۔ جس ملک میں جب اطمینان نہ ہو، جب سرحدوں کے اہلے والوں کو پورا یقین نہ ہو کہ کیا ہو سکتا ہے تو ملک میں ایمرجنسی خود ہی پیدا ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں کو روکنے کے لئے یہ ڈیفنس آف انڈیا

[شری اے۔ ایم۔ طارق]

ظلم ہے اور جرم ہے کہ اس ملک میں  
رہنے والے کسی آدمی کو پاکستانی  
کہا جائے۔ میں سمجھتا ہوں مسٹر  
سپرو اور آنرہبل پانڈے میڈی اس  
بات میں حمایت کرینگے کہ یہ بھی  
ایک بہت بڑا جرم ہے کہ علی محمد  
طارق کو پاکستانی کہہ کر بدنام کیا  
جائے۔

श्री प्रकाश नारायण सप्रू : मैंने कभी  
नहीं कहा ।

[شری اے۔ ایم۔ طارق : آپ کو  
میں نہیں کہتا ہوں۔ بہرحال کسی  
کی عزت کو اس کی جان و مال کو  
اور اس کے بچوں کو خطرہ میں ڈالنا  
یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور اس کی  
طرف خیال کرنا چاہئے۔ طارق کو  
نہ کہتے ہماریوں کہہ صاحب کو  
کہتے۔۔۔۔]

श्री प्रकाश नारायण सप्रू : उनको भी  
नहीं कहा ।

[شری اے۔ ایم۔ طارق : کسی  
مسلمان کو اس ملک میں پاکستانی  
کہہ اس کی جان و مال کو خطرہ  
میں ڈالنا یہ بھی ایک خطرناک  
سازش ہے اور جو ایسا کرے اس کے  
خلاف قینٹس آف انڈیا رولز کو فوراً  
استعمال کرنا چاہئے۔ صرف اس لئے  
کہ وہ اقلیت فرقہ کا ہے و کرشچین ہے  
مسلمان ہے و بدعہ ہے یا سکے ہے و اچھے  
سہاسی مقصد کے پھس نظر کسی

دوسرے ملک کا حامی قرار دیا جائے  
اور اس ملک میں فسادات کرائے  
جائیں اور ملک کے نظام کو خواب  
کہا جائے تو سوکار کا فرض ہے کہ ایسا  
کرنے والے اوں پر قانون استعمال  
کیا جائے۔

اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی  
دیکھنا ہے کہ ملک میں عام چیزیں  
جو دستیاب ہونی چاہئیں ان کے  
دام پہنچنے ہو گئے ہیں اور اس پر  
قینٹس آف انڈیا رولز استعمال کرنا  
چاہئے۔ دنیا کے تمام ملکوں میں  
ایسا ہوا ہے چہاں ایمرجنسی کا اعلان  
ہوا۔ ایمرجنسی کے معنی یہ  
نہیں ہیں کہ جو متخالف ہے جو  
اوریشن میں ہے اس پر اس کو استعمال  
کیا جائے۔ قینٹس آف انڈیا رولز کے  
معنی یہ ہیں کہ ملک کا اندرونی  
امن ہر قسم پر قائم رکھا جائے۔  
قینٹس آف انڈیا رولز کے یہ معنی  
نہیں ہیں کہ جو شخص سرکار کے  
خلاف نعرہ لگاتا ہے اس کو پکڑا جائے۔  
ایمرجنسی کے معنی یہ ہیں کہ جو  
ایکسیلائیٹ کرنے کی کوشش کرے اور  
دعایا کو پریشان رکھے اس پر قینٹس  
آف انڈیا رولز کا اطلاق ہونا چاہئے۔  
چاہے وہ قہمتوں کے بارے میں ہے چاہے  
وہ استوائیوں کے بارے میں ہو۔ چاہے  
وہ رسل و رسائل کو روکنے کے بارے میں  
ہو۔ یہاں ایک غلطی ضرور پڑھوئی ہے  
جو بعض دوستوں نے یہ کہا کہ ہم اس

کہ ایمرجنسی نہیں مانتے ہیں کہ  
وزیروں کے گھر میں شامی ہو تو اس  
میں بجلی لگائی جائے۔ اگر کہیں  
شادی ہوتی ہے تو ہم اس میں بجلی  
بھی لگاتے ہیں اور ہارٹی بھی دیتے  
ہیں۔ ہم ایک بہت بڑے ملک کے  
رہنے والے ہیں۔ انگریزوں کے زمانہ  
میں بھی ہال روم ڈانس ہوتے تھے اور  
لوگ نائٹ ڈکلب میں جاتے تھے۔  
ایک روم کے معیار کو بلند رکھنے کے لئے  
اور اپنے مارلس کو بلند کرنے کے لئے  
انسان کو یہ سب کرنا پڑتا ہے اور میں  
سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزیں  
ہمیں کرنی چاہئیں۔ ورنہ ہم لوگوں  
کو یہ معلوم ہوگا کہ شکست خوردہ  
ذہنیت پیدا ہو گئی ہے جو ہمیں  
ملک میں پیدا کرنی نہیں ہے۔ ہمیں  
اچھے لوگوں کو یہ نہیں بتانا ہے کہ ہم  
بالکل ہی ختم ہو گئے ہیں اور بالکل  
چھٹووں نے ہمیں کھا لیا ہے۔

نہیں۔ بلکہ ہم نے اچھے لوگوں کے  
ہاں میں ایک جذبہ پیدا کرنا ہے کہ  
ہم چھٹوؤں کے، پاکستانیوں کے حملہ کا  
مقابلہ کریں گے۔ ہر صاحب نے  
ابھی فرمایا ہے اور میں ان کی رائے کی  
قدر کرتا ہوں کہ اگر ہمارا معاملہ چھٹی  
کے ساتھ پر امن طریقہ پر اور باعزت  
طریقہ پر حل ہو جائے تو رآ کرنا  
چاہئے۔ اگر پاکستان کے ساتھ بھی  
یہ طریقہ پر ملے ہو جائے تو ہم کو  
ملے کرنا چاہئے اور یہ ہماری پالیسی  
3 R.S.—3.

کے مطابق ہے لیکن جہاں ہماری عزت،  
ہمارے ملک کی سالمیت پر اثر انداز  
ہو تو ہمیں اسے کہیں نہیں ماننا  
چاہئے وہ چھٹی ہو، پاکستان ہو، دنیا  
ہو۔ کہوں کہ اگر ہم ویسا کریں گے تو  
ہمارے ہندوستان کی شان اور ہندوستانی  
کی تاریخ کو بدلتا پڑتا ہے جو ہم  
نہیں بدلیں گے۔ کہوں کہ ہم  
ہندوستانی جانتے ہیں کہ ہمارے گلچر  
میں وہ بات شامل ہے۔ آج سے کئی  
سو برس پہلے ہندوستان پر سکندر اعظم  
کے حملہ کے ۲۰۰۰ برس کی شکست  
ہوئی تھی تو اس نے ہروس سے پوچھا۔  
میں دہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کروں؟  
اور ہروس نے کہا۔ ”وہی جو ایک  
بادشاہ کو بادشاہ کے ساتھ کرنا چاہئے۔“  
یہ ہندوستان کے گلچر کا ایک صرف  
نمونہ ہے۔ تو ہم دنیا کے لوگوں سے جو  
بات چیت کریں گے وہ ایک آزاد ملک  
کی حیثیت سے کریں گے۔ با عزت  
شہری کی حیثیت سے کریں گے۔ ہم  
وہ فیصلہ نہیں کرینگے جو ہمارے ملک  
کی سالمیت، ہماری تاریخ اور ہمارے  
حالات کے مطابق نہ ہو۔

سرکار سے مجھے اس بارے میں دو  
تین باتیں کہنی ہیں۔ قہقلس آف  
انڈیا رولز کا اطلاق ایسے لوگوں پر بھی  
ہونا چاہئے جو اخباروں کے ذریعہ  
کتابوں کے ذریعہ، تقریروں کے ذریعہ  
اس ملک کی سالمیت کو خطرہ میں  
قالتے ہیں اور اس میں کوئی راہت



[شری اے۔ ایم۔ طارق]

نہیں ہونی چاہئے۔ جب ہم یہ تھوڑی سی رعایت کر دیتے ہیں پھر ہمارے لئے ہوا مشکل ہوتا ہے کس کو پکڑیں۔ اگر طارق کوئی غلطی کرتا ہے تو اس پر باقاعدہ اس کا اطلاق ہونا چاہئے۔ اگر وہ تینفلس آف انڈیا دولہ میں آتا ہے تو مقدمہ چلنا چاہئے لیکن اگر وزیر صاحب نے سمجھا طارق تو اپنا دوست ہے تو پھر ہوا مشکل ہو جائے گا کسی پر ہاتھ ڈالنا۔ ہمارے لئے یہ درست نہیں ہے یہ کہنا کہ ہمارے چند لوگ جو وہاں بیٹھے ہیں وہ ہندوستان کے دشمن ہیں۔ چوسا کہ میں آپ کو یقین دلانا ہوں، ہاجپٹی صاحب مجھے افسد ہے ناراض نہیں ہوں کہ ہر مسلمان جو اس ملک میں بستا ہے وہ ہندوستان کا دشمن نہیں ہے اور ہر ہندو جو اس ہندوستان میں رہتا ہے وہ اس ملک کا لائل نہیں ہے۔ کہوں کہ لائلی کسی قوم کی، کسی مذہب کی وراثت نہیں ہے لہذا ان باتوں کو سرکار کو دیکھنا چاہئے۔ اگر کانگریس پارٹی کے اندر کوئی شخص کسی قسم کی سیاسی یا سماجی گڑبڑ کرتا ہے تو اس کو قانون کے سامنے کھڑا کرنا چاہئے ورنہ ہم اٹل بھاری ہاجپٹی کے ہاتھ پاؤں نہیں باندھ سکتے۔ اور جس وقت ہم نے اس کو باندھ دیا اس وقت ہم چلتا میں غلط رائے پیدا کرتے ہیں کہ یہ تو مخالفوں کو دبا دے ہوگا۔ تو

ایمپرنس کے معنی یہ ہیں کہ جو ملکی حالات کے مخالف کام کرتے ہیں ان کے بارے میں قانون کو کبھی نہیں دیکھنا چاہئے کہ کرلے والا کون ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ مذہب کیا ہے۔ اگر غلط کرتا ہے کوئی یہی کرتا ہے تو اس کو قانون کے سامنے کھڑا کرنا چاہئے۔

دوسری گزارش یہ ہے کہ چٹلے پھر ملکی اخبار نویس اس ملک میں آتے ہیں ان کے خلاف بھی اگر ہم کو شکایتیں ملیں اور وہ شکایتیں ایسی ہوں جو تینفلس آف انڈیا کے تحت آتی ہیں تو ہم کو کم سے کم اس شخص کو چٹلے کرنا چاہئے۔ میں نے کل ہوم منسٹر صاحب کی خدمت میں ایک بات کی طرفہ جو ایک چھوٹی بات نہیں ہے بڑی بات ہے، ان کی توجہ دلائی تھی۔ کھسور میں جب گڑبڑ ہوئی اس سے نہویارک ٹاسز کے اسپیشل کارپونڈنٹ کو کراچی سے فلائی کراکر دلی لایا گیا اور دلی سے کھسور بھیجا گیا۔ جب کہ میں نے یہاں دلی میں اپنا ایک کارپونڈنٹ مقرر ہے۔ He is meant for India. He has to report what is happening in India. اس نے ایسی غلط باتیں لکھیں جیسا کہ اس نے یہ لکھا کہ وہاں کے مسلمان ہندوؤں کے خلاف ہیں۔ ہندو سامراج واد کے خلاف ہیں۔ ہندو حصار آوروں کے خلاف ہیں۔ پھر

حال میں اسے غلط ہی نہیں—اگر یہ ان پارلیمنٹری نہ ہو۔ تو بہت بڑا جھوٹ کہتا ہوں۔ جب اس نے دیکھا تھا کہ اس جلوس میں ہندو، مسلمان، سکھ سبھی اکٹھے ہیں پھر بھی ایسی غلط باتیں کی۔ لیکن سرکار ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتی ہے۔ اپنا ڈسپیچ بھیجے کے بعد دوسرے دن وہ واپس کراچی چلا گیا۔ جب دلی میں نیویارک ٹائمز کا کارپونڈنٹ بیٹھا ہے تو کراچی سے کارپونڈنٹ کو آنے کی کہا ضرورت ہے، تو سرکار کو ان چیزوں پر بھی توجہ کرنی چاہئے۔ یہ سب چیزیں قیغلس آف انڈیا پالیسی میں آتی ہیں۔ کہیں کہ ان تمام چیزوں سے ہندوستان کی شہرت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ کسی شہر ملک میں بھٹے ہوئے کسی صاحب نے پڑھا کہ کشمیر کے مسلمانوں نے ہندوؤں کے خلاف ایجنڈیشن کیا ہے تو اس کا کیا اثر ہوگا۔ اور جہاں کہیں ہندو زیادہ ہیں وہاں مسلمانوں کی جان و مال کو اور جہاں مسلمان زیادہ ہوں وہاں ہندو کی جان و مال کو خطرہ ہے۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے تو نہ جانے امریکہ والے کیا کہیں گے۔ فوجی امداد کا کیا ہوگا۔ حالانکہ ہوگا وہاں کچھ نہیں۔ آپ صدر ناصر کو دیکھئے اس نے روس، انگریز و امریکہ سبھی سے امداد لی لیکن اہلی ساری شرطیں بھی ملوالیں

لیکن ہم جو مدد لیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ جس سے امداد لی ہے اس سے ہم نے فلامی پالی ہے۔ (Interruptions.)  
پولٹیکالی چھوڑئے . . .

(Time bell rings.)

ایک طرف ایسا ہوتا ہے نہ آسام کی سرحدوں پر بڑی گڑبڑ ہے۔ ہندو و مسلمان کی گڑبڑ ہے۔ پاکستان کی گڑبڑ ہے۔ چین کی گڑبڑ ہے لیکن کل کے ہی اخباروں میں تھا کہ ریاست جرملی سے کچھ لوگ آ رہے ہیں گارڈ ہلس میں ٹھہری ویزن کی فلم بنانے کے لئے۔ اب یہ سرکار کو دیکھنا چاہئے کہ جب ہماری سرحدوں پر اس وقت پاکستان کے ساتھ گڑبڑ ہے، چین سے گڑبڑ ہے، ریفوجیز آ رہے ہیں۔ جا رہے ہیں اسے موقع پر ایک فہرہ ملے گی ٹھہری ویزن کیمرا والے وہاں پہنچ جائیں گے۔ اب جب وہ فلم بن جائے گی اور ہندوستان کے باہر جائے گی تو پھر اتل بہاری باجپئی، مسٹر طارق، باجی صاحب سب شور کہیں گے اور سرکار کم کمی ہوں پتہ نہیں تھا۔ ان تمام چیزوں کا قیغلس آف انڈیا رولز کے ساتھ تعاقب۔ جب ایمرجنسی ہے تو صرف میرے اور باجپئی صاحب کے لئے ہی نہیں ہے۔ ایمرجنسی باہر کے لوگوں کے لئے بھی ہے۔

[شری اے - ایم - طارق]

جہاں آپ طے کرتے ہیں کہ اس ملک کے امن کو بگاڑنے کے لئے مسٹر ہاجپٹی اور طارق ہی سازش کر سکتے ہیں؟ آپ کو دیکھنا چاہئے کہ باہر کے لوگ بھی کچھ ایسے ہیں جن کو اس ملک میں سازش کرنے سے بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے :

THE DEPUTY CHAIRMAN: Fifteen minutes is the allotted time for discussion on Resolution. You wind up now.

[شری اے - ایم - طارق : میں ختم

کر رہا ہوں کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے : ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو کشمیر کے لوگوں نے یہ دکھایا ہے کہ ان میں مذہبی سیاسی اور سماجی ایکٹا ہے - دوسری طرف کچھ لوگوں نے سازشیں کیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ میں ایک ایسی مصیبت میں آ گیا ہوں خود ذاتی طور پر کہ -

زائد تلگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں

اتل بھاری صاحب کہتے ہیں اس کا نام علی محمد طارق ہے - انور صاحب یہ سمجھتے ہیں اس کا نام علی رام ہے -

[شری این - ایم - انور (مدرس) :

خواستخواہ مجھے کہیں لگے ہو - میں تو آپ کو کچھ نہیں سمجھتا -

[شری اے - ایم - طارق : میں

نے کہا اسی لحاظ سے آپ کا نام آ جائے - تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں کشمیر کی بات کرتا ہوں میں جانتا ہوں ہماری سرحدوں کے اندر کڑ بڑ ہوتی ہے اور بہت زوروں سے ہوتی ہے - کشمیر سے پاکستان میں آدمیوں کو کھینچ کر لے جاتے ہیں - ابھی ۲۰ آدمیوں کو لے گئے

یعنی ایک بڑے ملک میں ۲۲ آدمی ۱۰ منٹ میں مار دیئے جائیں تو

یہ ایمرجنسی نہیں تو کیا ہے -

لیکن ایمرجنسی کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ گانڈ پر آپ ایمرجنسی لکھیں - اس کے معنی یہ ہوں کہ اس کا جائز طور پر استعمال کریں ہم یہ معلوم کریں کہ ۲۲ آدمیوں کو جو ایبھوش کیا گیا ہے اس کے پھتچے سازش کیا ہے - ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ ایکسپلوزنس اور بمبارنگ کیسز ہو رہے ہیں - اب سرکار خرد کہہ رہی ہے پاکستان ہمارے ہوائی جہازوں کو غلط راستہ بتاتا ہے اور یہی بہت سی باتیں ہیں -

یہاں بہت سے غہر ملکی ایجنٹ بیٹھے ہیں جو مقامی لوگوں سے مل کر ہمارے ٹینفس کے سوومنت سے واقفیت رکھتے ہیں اس سے انکار نہیں ہو سکتا - تو ان چیزوں کو روکنے میں اس قانون کا استعمال بے حد ضروری ہے - اس قانون کا استعمال صرف مخالف جماعتوں کو

دبانے کے لئے نہیں ہونا چاہئے۔  
 چاہے مسلم لیگ ہو، جن مسلم ہو، اگلی  
 ہو اس ملک میں جو اندرونی طور  
 پر سازش کرتے ہیں ان کو دبانے  
 کی بے حد ضرورت ہے۔ ان الفاظ  
 کے ساتھ میں اس ریجولیشن کی  
 مخالفت کرتا ہوں لیکن یہ ایک  
 دفعہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان  
 کی رہائی کی پروردگار حسالت کرتا  
 ہوں۔

†[شری ए० एम० तारिक (जम्मू और  
 काश्मीर) : मैडम डिप्टी चेयरमैन, जहाँ तक  
 इस रेजोल्यूशन का ताल्लुक है मैं इसकी  
 मुखालफत करता हूँ ।

श्री प्रकाश नारायण सधू : पूरी मुखाल-  
 फत तो नहीं करेंगे ?

श्री ए० एम० तारिक : आधी कलंगा  
 लेकिन जहाँ तक इस चीज का ताल्लुक है  
 जितने नजरबन्द हैं इस मुल्क में और काफी  
 देर से हैं उनको छोड़ देना चाहिए अगर वो  
 छोड़े नहीं जा सकते हैं तो उनके खिलाफ जो  
 शिकायतें हैं उनको अदालत में लाना चाहिये ।  
 इससे एक सूरत यह पैदा हो जायेगी कि  
 मुल्क के जो चन्द लोग या चन्द जमायतें  
 डिफेंस आफ इंडिया रूल्स की मुखालफत  
 सिर्फ इसलिए करती हैं कि इस मौजूदा सरकार  
 ने उसे लागू किया है उनको लोगों में  
 यह गलत बोलने का मौका नहीं मिलेगा  
 कि डिफेंस आफ इंडिया रूल्स मौजूदा हुकुमत  
 ने सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए लागू  
 किए । बल्कि उनको यह यकीन हो जायेगा  
 और हमें आशाम को भी यह बताना है कि  
 डिफेंस आफ इंडिया रूल्स की जरूरत इस  
 मुल्क में है, थी और आगे भी कुछ मुद्दत के लिये  
 रहेगी । एमरजेंसी के माने ये नहीं हैं कि

हमारे मुल्क में जंग हो तब एमरजेंसी  
 पैदा होती है । एमरजेंसी उस वक़्त भी  
 पैदा होती है जब मुल्क की सरहदों को खतरा  
 हो या मुल्क के अन्दर कुछ गैर मुल्की लोग  
 मुल्क के रहने वालों की मदद से अफ़रा-तफ़री  
 फैलाते हैं, साजिशें करने हों और मुल्क के  
 रस्ल व रसायल और खूराक के पहुंचाने के  
 इन्तजामात में या दूसरी चीजों को जिनका  
 शहरी ज़िन्दगी पर असर पड़ता हो रोकना  
 भी एमरजेंसी है । कुछ नहीं तो इस माहौल  
 को कायम रखना निहायत ज़रूरी है ।  
 मैं उन दोस्तों के साथ इत्तफाक नहीं कर सकता  
 जो यह कहते हैं कि मुल्क में एमरजेंसी न  
 हो । चीनी हमले से पहले भी इस मुल्क में  
 एमरजेंसी थी और चीनी हमले के बाद तो  
 एमरजेंसी की बेहद जरूरत है । इस वक़्त  
 हमारे सामने कोई ऐसी जमानत नहीं है  
 कि चीन और पाकिस्तान अलग अलग या  
 मिल कर हमारी सरहदों पर हमला नहीं  
 करेंगे । अगर आज हिन्दुस्तान को यह  
 जमानत मिल जाय कि पाकिस्तान और चीन  
 हिन्दुस्तान के इलाकों पर हमला नहीं करेंगे  
 और पाकिस्तान के लोग हिन्दुस्तान की  
 सरहदों के अन्दर गड़बड़ करने की कोशिश नहीं  
 करेंगे तो एमरजेंसी बजाते खुद खत्म हो जायेगी  
 लेकिन इन दोनों चीजों की हमारे पास कोई  
 जमानत नहीं है बल्कि अगर हम दयानत  
 दाराना और एक हिन्दुस्तानी की हैसियत  
 से यह छोड़ कर के कि हम किस जमायत  
 के अन्दर हैं इस बात को देखें तो हमको यह  
 यकीन हो जाता है कि इस मुल्क में एमरजेंसी  
 है ।

मैं मि० भूपेश गुप्त की मुखालफत इस  
 लिये नहीं कर रहा हूँ कि वे मुख्तलिफ  
 जमायत के मੈम्बर हैं या लीडर हैं और उन्होंने  
 यह रेजोल्यूशन पेश किया है बल्कि मैंने  
 अक्सर मौकों पर उनकी हिमायत की है और  
 मेरे दोस्त आनरेबल पांडे यह समझते हैं कि  
 मैं उनका ज्यादा साथी हूँ और पांडे साहब का  
 कम हूँ लेकिन हकीकत यह है कि जब मुल्क

[श्री ए० एम तारिक]

का मामला सामने हो तो उसमें अफराद की दोस्ती के माने कुछ नहीं रहते । मुल्क की अहमियत के ख्याल से आप पिछले दो महीनों में दयानतदारी से देखें कि काश्मीर के अन्दर कितने ऐसे केसिस् हुए हैं तो आपको यकीन हो जायगा कि इस मुल्क में एमरजेंसी की जरूरत है । पाकिस्तान की साजिशों के खिलाफ या चीन की साजिशों के खिलाफ ही एमरजेंसी की जरूरत नहीं है बल्कि इसलिये भी एमरजेंसी की जरूरत है कि इस मुल्क में कुछ लोग मजहब के नाम पर, जात-पात के नाम पर, सोशलिज्म और सरमायादारी के नाम पर अन्दरूनी गड़बड़ करना चाहते हैं और गड़बड़ हुई भी है । जैसे बंगाल में हुई और दिल्ली में स्ट्राइकें हो रही हैं, बड़े बड़े कारखानों में स्ट्राइकें हो रही हैं, तो आज इस मुल्क को इस वक्त जंगी हालात का सामना है । हमारी सरहदों पर एक तरफ हमारी फौजें हैं और दूसरी तरफ चीनी-फौजें हैं और एक तरफ हमारी फौजें हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौजें और हालात ऐसे हैं कि कोई यह नहीं कह सकता है कि किस वक्त क्या हो जाय । जिस मुल्क में जब इतमीनान न हो, जब सरहदों के रहने वालों को पूरा यकीन न हो कि क्या हो सकता है तो मुल्क में एमरजेंसी खुद ही पैदा हो जाती है । इन चीजों को रोकने के लिये यह डिफेंस आफ इंडिया रूल्स लागू किए गए हैं और यह इसलिये लागू किये गये हैं कि मुल्क में खुराक की कीमतें न बढ़ें और मुल्क में रस्लो-रसायल को नुकसान न पहुंचे और मुल्क में मजहब के नाम पर फसादात न कराये जायें ।

श्री प्रकाश नारायण सप्रू : यह सब चीजें हो रही हैं ।

श्री ए० एम० तारिक : यह सब चीजें हो रही हैं, इसमें मैं आपसे इत्फाक करता

हूँ लेकिन हुक्मत की तबज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जिन चीजों को रोकने के लिये इसको लागू किया गया था, उनके रोकने में इसका सही हद तक इस्तेमाल नहीं किया गया है । इसकी कई वजुहात हो सकती हैं । एक वजह यह है कि हमारा जो कल्चर है वो बदकिस्मती से कई हजार साल पुराना है और बयक वक्त हम इसको खत्म भी नहीं कर सकते हैं । हमारा कल्चर एक शराफत का है, बुजुर्गी का है और खादारी का है । और तीनों चीजों में हम भारे जाते हैं ।

एक माननीय सदस्य : कौन-कौन चीजें ?

श्री ए० एम० तारिक : बुजुर्गी, शराफत और खादारी और इसकी मिसाल मैं खुद खड़ा हूँ । तो इन तीनों चीजों से हमें नुकसान होता है । मैं यह समझता हूँ कि यह एक बहुत बड़ा जल्म है और जर्म है कि इस मुल्क में रहने वाले किसी आदमी को पाकिस्तानी कहा जाय । मैं समझता हूँ मि० सप्रू और आनरेबल पांडे मेरी इस बात में हिमायत करोगे किये भी एक बहुत बड़ा जर्म है कि अली मुहम्मद तारिक को पाकिस्तानी कह कर बदनाम किया जाय ।

श्री प्रकाश नारायण सप्रू : मैंने कभी नहीं कहा ।

श्री ए० एम० तारिक : आपको मैं नहीं कहता हूँ । बहरहाल किसी की इज्जत को, उसकी जानोमाल को और उसके बच्चों को खतरे में डालना ये एक बहुत बड़ा जर्म है और इसकी तरफ ख्याल करना चाहिये । तारिक को न कहिये, हुमायूँ कविर साहब को कहिये . . .

श्री प्रकाश नारायण सप्रू : उनको भी नहीं कहा ।

श्री ए० एम० तारिक : किसी मुसलमान को इस मुल्क में पाकिस्तानी कह कर उसकी जानोमाल को खतरे में डालना यह भी ए०

खतरनाक साजिश है और जो ऐसा करे उसके खिलाफ डिफेंस आफ इंडिया रूल्स को फौरन इस्तेमाल करना चाहिये। सिर्फ इस लिये कि वो अकलीयत फिरके का है, क्रिश्चन है, मुसलमान है, बौद्ध है या सिख है, वो अपने सियासी मकसद के पेबेनजर किसी दूसरे मुल्क का हामी करार दिया जाये और इस मुल्क में फसादात कराये जायें और मुल्क के निजाम को खराब किया जाय तो सरकार का फर्ज है कि ऐसा करने वाले लोगों पर कानून का इस्तेमाल किया जाय।

इसके साथ साथ हमको यह भी देखना है कि मुल्क में आम चीजें जो दस्तयाब होनी चाहिये उनके दाम मंहगे हो गए हैं और इस पर डिफेंस आफ इंडिया रूल्स इस्तेमाल करना चाहिये। दुनिया के तमाम मुल्कों में ऐसा हुआ है जहां एमरजेंसी का ऐलान हुआ। एमरजेंसी के माने यह नहीं है कि जो मुबालिफ है, जो अपोजीशन में है, उस पर इसको इस्तेमाल किया जाय। डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के माने ये हैं कि मुल्क का अन्दरूनी अमन हर कीमत पर कायम रखा जाये। डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के माने ये नहीं हैं कि जो शास्त्र सरकार के खिलाफ नारा लगाता है उसको पकड़ा जाय। एमरजेंसी के माने ये हैं कि जो एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करे और रियाया को परेशान रखे उस पर डिफेंस आफ इंडिया रूल्स का इतलाक होना चाहिये, चाहे वो कीमतों के बारे में, चाहे वो स्ट्राइकों के बारे में हों, चाहे वो रेलवेसायल को रोकने के बारे में हों। यहाँ एक गलती जरूर हुई है जो बाज दोस्तों ने यह कहा कि हम इसको एमरजेंसी नहीं मानते हैं कि वजहों के घर में शादी हो तो इसमें बिजली लगाई जायें। अगर कहीं शादी होती है तो हम उसमें बिजली भी लगाते हैं और पार्टी भी देते हैं। हम एक बहुत बड़े मुल्क के रहने वाले हैं। अंग्रेजों के जमाने में भी बालरूम डान्स होते थे और लोग नाइट क्लब में जाते थे। एक कौम के भियार

को बुलन्द रखने के लिये और अपने मोरल्स को बुलन्द करने के लिये इन्सान को यह सब करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि इस किस्म की चीजें हमें करनी चाहिये। वरना हम लोगों को यह मालूम होगा कि शिकस्त खुरदा जेहनियत पैदा हो गई है जो हमें मुल्क में पैदा करनी नहीं है। हमें अपने लोगों को यह नहीं बताना है कि हम बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं और बिल्कुल चीनियों ने हमें खा लिया है।

नहीं, बल्कि हमने अपने लोगों के दिलों में एक जज्बा पैदा करना है कि हम चीनियों के, पाकिस्तानियों के हमले का मुकाबिला करेंगे—सप्रू साहब ने अभी फरमाया है और मैं उनकी राय की कदर करता हूँ कि अगर हमारा मामला चीन के साथ पुरअमन तरीका पर और बाइज्जत तरीका पर हल हो जाये तो फौरन करना चाहिए। अगर पाकिस्तान के साथ भी बाइज्जत तरीका पर तै हो जाये तो हमको तै करना चाहिए। और यह हमारी पोलिसी के मुताबिक है लेकिन जहां हमारी इज्जत, हमारे मुल्क की सालमियत पर असर अन्दाज हो तो हमें उसे कभी नहीं मानना चाहिये चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, दुनिया हो। क्योंकि अगर हम बैसा करेंगे तो हमारे हिन्दुस्तान की शान और हिन्दुस्तान की तारीख को बदलना पड़ता है जो हम नहीं बदलेंगे। क्योंकि हम हिन्दुस्तानी जानते हैं कि हमारे कल्चर में वो बात शामिल है। आजसे कई सौ वर्ष पहले हिन्दुस्तान पर सिकन्दरेआजम के हमले के आगे पोरस की शिकस्त हुई थी तो उसने पोरस से पूछा “मैं आपके साथ क्या सलूक करूँ?” और पोरस ने कहा—“वही जो एक बादशाह को बादशाह के साथ करना चाहिए।” यह हिन्दुस्तान के कल्चर का एक सिर्फ नमूना है। तो हम दुनिया के लोगों से जो बातचीत करेंगे वो एक आजाद मुल्क की हैसियत से करेंगे, बाइज्जत शहरी की हैसियत से करेंगे। हम वो फँसला नहीं करेंगे जो हमारे मुल्क की

[श्री ए० एम० तारिक]

सालमियत, हमारी तारीख और हमारे हालात के मुताबिक न हो।

सरकार से मुझे इस बारे में दो तीन बातें कहनी हैं। डिफेंस आफ इंडिया क्लस का इस्लाम ऐसे लोगों पर भी होना चाहिए जो अखबारों के जरिए, किताबों के जरिए, तकरीरों के जरिए, इस मुल्क की सालमियत को खतरे में डालते हैं और इसमें कोई रिश्कायत नहीं होनी चाहिए। जब हम यह थोड़ी सी रिश्कायत कर देते हैं फिर हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि किसको पकड़े। अगर तारिक कोई गलती करता है तो उस पर शाकायदा इसका इस्लाम होना चाहिए। अगर वो डिफेंस आफ इंडिया क्लस में आता है तो मुकदमा चलना चाहिए लेकिन अगर बशीर साहब ने समझा तारिक तो अपना दोस्त है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जायेगा किसी पर हाथ डालना। हमारे लिए यह दुस्त नहीं है यह कहना कि हमारे चन्द लोग जो वहाँ बैठे हैं वो हिन्दुस्तान के दुश्मन हैं। जैसा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बाजपेयी साहब मझे उम्मीद है नाराज नहीं होंगे हर मुसलमान जो इस मुल्क में बसता है वो हिन्दुस्तान का दुश्मन नहीं है और हर हिन्दू जो इस हिन्दुस्तान में रहता है वो इस मुल्क का लायल नहीं है। क्योंकि लायलटी किसी कोम की, किसी मजहब की विरासत नहीं है, लिहाजा इन बातों को सरकार को देखना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी के अन्दर कोई शक्स किसी किस्म की सियासी या समाजी गड़बड़ करता है तो उसको कानून के सामने खड़ा करना चाहिए वरना हम अटल बिहारी बाजपेयी के हाथ-पांव नहीं बांध सकते और जिस वक्त हमने उसको बांध दिया उस वक्त हम जनता में गलत राय पैदा करते हैं कि यह तो मुखालिफों को दबा रहे हैं। तो एमरजेंसी के माने ये हैं कि जो मल्की हालात के मुखालिफ काम करते हैं उनके बारे में कानून को कभी

नहीं देखना चाहिए कि करने वाला कौन है इसका अकीदा क्या है, मजहब क्या है। अगर गलत करता है, कोई भी करता है तो उसको कानून के सामने खड़ा करना चाहिए।

दूसरी गुजारिश यह है कि जितने गैर-मल्की अखबारनवीस इस मुल्क में आते हैं उनके खिलाफ भी अगर हमको शिकायतें मिलें और वो शिकायतें ऐसी हों जो डिफेंस आफ इंडिया के तहत आती हैं तो हमको कम से कम उस शक्स को वार्न करना चाहिए। मैंने कल होम मिनिस्टर साहब की खिदमत में एक बात की तरफ जो एक छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है उनकी तबज्जो दिलाई थी। काश्मीर में जब गड़बड़ हुई उस समय न्यूयार्क टाइम्स के स्पेशल कारसपांडेंट को कराची से फ्लाई करा कर दिल्ली लाया गया और दिल्ली से काश्मीर भेजा गया। जबकि उनका यहाँ दिल्ली में अपना एक कारसपांडेंट मौजूद है।

He is meant for India. He has to report what is happening in India.

तो उसने ऐसी गलत बातें लिखीं जैसा कि उसने यह लिखा कि वहाँ के मुसलमान हिन्दुओं के खिलाफ हैं, हिन्दू साम्राज्यवाद के खिलाफ है, हिन्दू हमलावरों के खिलाफ हैं। बहरहाल मैं इसे गलत ही नहीं—अगर यह अन्तर्गालिया-मेंटरी न हो तो—बहुत बड़ा झूठ कहता हूँ। जब उसने देखा था कि इस जलूस में हिन्दू-मुसलमान-सिख सभी इकट्ठे हैं फिर भी ऐसी गलत ब्यानी की। लेकिन सरकार उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेती है। अपना डिसपैच भेजने के बाद दूसरे दिन वो वापिस कराची चला गया। जब दिल्ली में न्यूयार्क टाइम्स का कारसपांडेंट बैठा है तो कराची से कारसपांडेंट को आने की क्या जरूरत है, तो सरकार को इन चीजों पर भी तबज्जा करनी चाहिये। यह सब चीजें डिफेंस आफ इंडिया एक्ट में आती हैं। क्योंकि इन तमाम चीजों से हिन्दुस्तान की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। किसी गैर-मुल्क में बैठे हुए किसी साहब ने पढ़ा कि काश्मीर के मुसलमानों

ने हिन्दुओं के खिलाफ एजिटेशन किया है तो उसका क्या असर होगा और जहाँ कहीं हिन्दू ज्यादा हैं वहाँ मुसलमानों की जान व माल को और जहाँ मुसलमान ज्यादा हैं वहाँ हिन्दू की जान व माल को खतरा है। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर हम इसके खिलाफ एक्शन लेंगे तो न जाने अमरीका वाले क्या कहेंगे। फौजी इमदाद का क्या होगा। हालाँकि होगा-वोगा कुछ नहीं। आप सदर नासिर को देखिये, उसने रूस, अंग्रेज, अमरीका सभी से इमदाद ली लेकिन अपनी सारी शर्तें भी मनवा लीं लेकिन हम जो मदद लेते हैं तो सोचते हैं कि जिससे इमदाद ली है उससे हमने गुलामी पा ली है। (Interruptions) पोलिटिकली छोड़िये . . .

(Time bell rings.)

एक तरफ ऐसा होता है कि आसाम की सरहदों पर बड़ी गड़बड़ है। हिन्दू मुसलमान की गड़बड़ है, पाकिस्तान की गड़बड़ है, चीन की गड़बड़ है, लेकिन कल के ही अखबारों में था कि वेस्ट जर्मनी से कुछ लोग आ रहे हैं गारू हिल्स में टेलिविजन की फिल्म बनाने के लिये। अब ये सरकार को देखना चाहिये कि जब हमारी सरहदों पर इस वक्त पाकिस्तान के साथ गड़बड़ है, चीन से गड़बड़ है, रिपयूब्लिस आ रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे मौके पर एक गैरमुल्की टेलिविजन कैमरा वाले वहाँ पहुँच जायेंगे। अब जब वह फिल्म बन जायेगी और हिन्दुस्तान के बाहर जायेगी तो फिर अटल बिहारी वाजपेयी, मिस्टर तारिक, याजी साहिब सब शोर करेंगे और सरकार कहेगी हमें पता ही नहीं था। इन तमाम चीजों का डिफेंस आफ इंडिया रूल्स के साथ ताल्लुक है, जब एमरजेंसी है तो सिर्फ मेरे और वाजपेयी साहिब के लिये ही नहीं है, एमरजेंसी बाहर के लोगों के लिये भी है। जहाँ आप तै करते हैं कि इस मुल्क के अमन को बिगाड़ने के लिये मिस्टर वाजपेयी और तारिक ही साजिश कर सकते हैं, आपको देखना चाहिये कि बाहर के लोग भी कुछ ऐसे हैं जिन को इस

मुल्क में साजिश करने में बहुत बड़ा फायदा होता है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Fifteen minutes is the allotted time for Resolutions. You wind up now.

श्री ए० एम० तारिक : मैं खत्म कर रहा हूँ। काश्मीर में जो कुछ हुआ है। एक तरफ अगर आप देखें तो काश्मीर के लोगों ने ये दिखाया है कि उनमें मजहबी, सियासी और समाजी एकता है। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने साजिशें कीं और बदकिस्मती ये है कि मैं एक ऐसी मुसीबत में आ गया हूँ खुद जाती तौर पर कि—

जाहिदे तंग नज़र ने मुझे काफ़िर जाना और काफ़िर यह समझता है मुसलमान हूँ मैं।

अटल बिहारी साहब कहते हैं कि इसका नाम अली मोहम्मद तारिक है। अनवर साहब यह समझते हैं इसका नाम अली राम है।

श्री एन० एम० अनवर : क्वाहमक्वाह मुझे क्यों लाते हो। मैं तो आपको कुछ नहीं समझता।

श्री ए० एम० तारिक : मैंने कहा इसी लिहाज से आपका नाम आ जाये। तो मैं यह समझता हूँ कि मैं जब काश्मीर की बात करता हूँ मैं जानता हूँ हमारी सरहदों के अन्दर गड़बड़ होती है और बहुत जोरों से होती है। काश्मीर से पाकिस्तान से आदमियों को खेंच कर ले जाते हैं। अभी २२ आदमियों को ले गये। यानी एक बड़े मुल्क में २२ आदमी १० मिनट में मार दिये जायें तो यह एमरजेंसी नहीं तो क्या है। लेकिन एमरजेंसी के माने सिर्फ ये नहीं हैं कि कागज़ पर आप एमरजेंसी लिखें। इसके माने ये हैं कि इसका जायज़ तौर पर इस्तेमाल करें। हम यह मालूम करें कि २२ आदमियों को जो एम्बुश किया गया है इसके पीछे साजिश क्या है। हमने इससे पहले कहा था कि एक्सपोज़िशन और





کہیں کہ ہمیں ایمرجلسی کی آپ  
 کہا ضرورت ہے - ذرا ملاحظہ فرمائیے  
 ان کا ریزولوشن جس میں آپ کہتے  
 ہیں -

"This House is of opinion that  
 having regard to the improved situ-  
 ation in the country the state of  
 emergency should now be ended."

آپ کے دماغ کو کہا ہوا ہے - انکو  
 کس نے کہا کہ سچویشن ہماری  
 امپروو ہو چکی ہے - میں نہیں  
 سمجھتا کہ کوئی عاقل یا دانش مند  
 اس صورت حال کو امپروو ملٹ کہے گا -  
 ساری دنیا جانتی ہے کہ قریب میں  
 جو ملاقاتیں ہوئیں پریذیڈنٹ  
 ایوب خان کی اور مسٹر چو این لئی  
 کی، ان ملاقاتوں نے بعد بھی ہمارے  
 پاس یہ احساس نہیں کہ حالتیں  
 ہمارے ملک کی بہت ہی بگڑتی  
 جا رہی ہیں -

مجھے بہت ہی صدمہ ہو رہا ہے  
 کہ میرے بھارے دوست مسٹر باجپٹی،  
 لیڈر جنرل سنگھ کو کہا ہوا - قاصر نے ک  
 خوب کہا :-

دل نادان قصہ ہوا کہا ہے  
 آخر اس درد کی دوا کہا ہے

وہ بھی اس خیال کے ہیں کہ ہمارے  
 یہاں اس وقت ایمرجلسی کی ضرورت  
 نہیں ہے - مجھے بہت ہی دکھ ہو  
 رہا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ حق  
 تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا - انہیں

نے جو جو باتیں یہاں پیش کیں  
 میں ماننا ہوں کہ سہول لبرٹیز کے ہم  
 علم بردار ہیں اور جمہوریت کے  
 علم بردار ہونے کی حیثیت سے ہمارے  
 محترم بزرگ ہی - ایسی - سپرو کو  
 میں مبارکباد دیتا ہوں کہ سہول  
 لبرٹیز کی جہاں تک ہو سکے ہم  
 ضرورت سے زیادہ حفاظت کریں -  
 شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا ملک  
 ہو جہاں ایسا بہترین ایکسپریمنٹ  
 کیا جا رہا ہو جمہوریت کا جیسا کہ  
 ہمارے یہاں ۳۵ کروڑ اشخاص کر  
 رہے ہیں - ہم نے مکمل آزادی دی  
 ہے - ذرا غور سے آپ اخبارات کا  
 مطالعہ فرمائیے - خصوصاً وہ اخبار جو  
 اہلی اہلی مقامی زبان میں شائع  
 ہوتے ہیں - کبھی ہندی میں،  
 کبھی اردو میں - کبھی غور فرمائیے  
 کہ کتنی ایسی اشتعال انگیز باتیں  
 ان میں لکھی جاتی ہیں - کتنی  
 فتنہ و فساد کی باتیں لکھی جاتی  
 ہیں - کبھی کسی کے گھریلو  
 اسسٹنٹس ہوتا ہے، چاہے وہ منسٹر  
 ہو، چاہے وہ کچھ ہو - جب ایمرجلسی  
 والے اس قسم کی حکومت کی مشاورت  
 میں، حکومت کی مخالفت میں،  
 ایسے ایسے جذبات ابھارتے ہیں جس  
 سے فسادات ہوتے ہیں تو کہا آپ یہ  
 سمجھتے ہیں کہ حکومت مخالف  
 دیکھتی رہے - اور کوئی کارروائی ان  
 پر نہ کرے -

[شری این - اہم - انور]

مہتمم قہقی چہرہ میں - میں تو کہتا ہوں اور میرا دعویٰ ہے کہ حکومت نے برابر طور پر انتظامی کارروائی نہیں کی - کلکتہ کے حادثہ میں یہی کہونکا کہ ایسے اخبار جن کا رات دن یہی پڑھتا ہے کہ مختلف قوموں کے درمیان قتلہ و فساد پیدا کریں - ہر ایک کے ایمان پر ہر ایک کی مصیبت پر ہر ایک کی وفاداری پر بدگمانی کی جائے - آخر اس قتلہ اور اس زہر کی حد کہا ہے - ہم آپ سے درخواست کرتا چاہتے ہوں - میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب میں ہندوستان کے اس موجودہ نازک دور کا ذکر کرتا ہوں تو کبھی کلکتہ میں کو آتا ہے - کہ ہماری حالت آگے چل کر کہا سے کہا بدلے گی - جو حالت اس سال جنوری میں تھی وہ فروری میں کہاں سے کہاں تک بگڑ گئی - اس سہیلہ مارچ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مارچ سہیلہ میں آفت اور بڑھ گئی یا کم ہوگئی - اگر کسی سے پوچھا جائے -- اور آپ جانتے ہیں کہ شہر کے امن و امان کے لیے ہر جگہ فائر بریکنگ رکھے جاتے ہیں - فائر انجنوں کا ہونا ضروری ہے کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ ہر لمحہ کتنے قتلہ و فساد ہوتے ہیں - کہیں ان کی آن میں آگ لگ جائے تب اس فائر انجن

کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں - اگر ہم نے ایمرجنسی کو اسٹیجیوٹ بک میں رکھ دیا ہے تو اس سے ہم کو بہت کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے اور قربانی کے بغیر ہم آزادی کو بحال نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں کسی انفرادی اور کسی پارٹی یا گروپ کی اہمیت نہیں ہے - جیسا کہ ہمارے مستترم دوست طارق صاحب نے بڑی خوبی سے بیان فرمایا - یہ جو سوال ہے یہ ہمارے دیش کا سوال ہے اس ملک کے امن و امان کا سوال ہے ملک کی سلامتی کا سوال ہے - کہوں کہ آج ملک خطرہ میں ہے - جہلم ہے ہماری زندگی جب کہ یہ ملک آفت میں ہے - چاروں طرف سے آفت ہی آفت ہے - دنیا کی بہت سی طاقتوں مختلف طریقوں سے اس کے چاروں طرف جمع ہو رہی ہیں اور نہ جانے آگے چل کر ہندوستان کی عظیم الشان جمہوریت پر کہا حملہ ہونے والا ہے - بہت سی باتیں ہر جگہ سنتے آتے ہیں کہ مختلف ممالک کے جو اخبار ہیں ان میں یہ لکھا جاتا ہے کہ ہندوستان اتنا بڑا دیس ہے اور ہندوستان کی مختلف قوموں کا اس قدر مل جل کر رہنا یہ بھی کسی کی آنکھوں میں گھٹکتا ہے - ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اس موقع پر یہی سب سے بڑا تاریخی منظر پیش نظر ہو کہ ہندوستان میں مختلف قومیں اپنے اتفاق و اتحاد سے . . .

(Interruptions)

کل اور آج کی بات چھوڑنے - سیکولرزم -  
 یہ تو پندرہ سال کا ہودا ہے - یہاں  
 ہندو دھرم کی وجہ سے پانچ ہزار دھرم  
 سے مختلف قوموں ملتی چلتی آ رہی  
 ہیں اور یہ ہمارا اسپرچول ہو رہا ہے  
 جو کہ دنیا کے لئے ایک نمونہ ہے -  
 یورپ میں بے شک عیسائی مذہب کے  
 لوگ ہیں لیکن صرف ایک مذہب  
 اور ایک کلیچہ کے ان کا لباس ایک  
 ہے ، ان کی مانتیں ایک ہیں ،  
 ان کے کھانے پھلے کا ڈھنگ ایک ہے  
 بلکہ ان کا طرز زندگی سب ایک ہے  
 لیکن زبان کا تقاضہ ہے کہ یورپ میں  
 اتنی زبان کی دیواریں کھڑی ہیں  
 پہلی اتنی قومیں ہیں کوئی جرمن  
 ہیں ، کوئی فرنچ ہیں ، کوئی سوئس  
 ہیں ، کوئی برٹش ، کوئی ڈچ ،  
 کوئی لویڈ ہیں ، کئی قومیں ہیں ،  
 مختص اس لئے کہ ان کی زبان کا  
 تقاضہ ہے - باوجود اس کے کہ ہمارے  
 ملک میں پندرہ سولہ زبانیں ہیں  
 باوجود اس کے کہ ہمارے ملک میں  
 ۱۰ یا ۱۲ قومیں ہیں ، باوجود اس  
 کے کہ ہمارا طرز زندگی جھڑبڑ میں  
 ایک طریقہ کا ہے اور شمال میں کئی  
 طریقہ کا ہے - باوجود اس کے کہ  
 ہمارے باہمی رسم و ریت کھانا پینا  
 دھن سون کپڑے کپڑے جدا ہیں  
 باوجود ان تمام تفرقات کے ایک کرشمہ  
 ہے ایک معجزہ ہے ، یہ دنیا کے لئے  
 ایک نمونہ ہے کہ ہندوستان ایک  
 خوبصورت چلسستان ہے جس میں

رنگ رنگ کے پھول ہیں -  
 سارے جہاں سے اچھا ہندوستان  
 ہمارا -  
 ہم بلبلوں میں اس کی یہ  
 گلستان ہمارا -  
 مذہب نہیں سکھانا آپس میں  
 بھڑکھٹا -  
 ہندی میں ہم وطن ہے  
 ہندوستان ہمارا -  
 یہ نمونہ دنیا کے کسی ملک نے نہیں  
 نہیں کیا - یورپ اور امریکہ کے لوگ  
 جو ہمیں سبق دیتے ہیں سلامتی کا ،  
 اتفاق کا ، اقتصاد کا ، کیا ان کے ہاں  
 اس طرح کے مسئلے نہیں ہوتے ؟  
 امریکہ میں گورے اور کالے لوگ جو  
 مختصر تعداد میں ہیں لیکن اس  
 قدر وہاں ریشہل، کھلیکس کے معاملہ  
 ہوتے ہیں باوجود اس کے کہ کلسٹی  
 تھوڑی ہیں حکومت نے مساوات کو  
 رکھی ہے - سارے فرقہ جیس کی  
 بد نظمی کا دنیا کو علم ہے اب وہ  
 ہمیں سبق دینے آیا ہے -

کعبہ کس ملہ سے چارکے غالب -  
 شرم تم کو مگر نہیں آتی -

یہ ہندوستانی ہیں جو ساری دنیا کو  
 علم و ادب کا سبق دیتے آئے ہیں - یہ وہ  
 ہندوستان ہے جس نے ساری دنیا کو اسی  
 و اسان کا سبق دیا - یہ وہ ہندوستان  
 ہے جو دنیا کو اتفاق و اقتصاد کا نمونہ ہزار  
 برس سے دینا آ رہا ہے ، یہ کوئی پختہ  
 جواہرلال نہرو کا سبق نہیں ہے سیکولرزم

[شری این - ایم - انور]  
 کا + یہ ایسا ماحول ہے جیسے ہماری  
 سرزمین میں ہمارے آب و اجداد نے  
 بحال رکھا - مبارک ہے - آفرین  
 آفرین - آفرین -

سبق پڑھ پھر عدالت کا +  
 شجاعت کا + عدالت کا -  
 لہا جالٹا تھو ہے کام دلہا  
 کی امامت کا -

ایسے ایک سماج کو جب خطرہ دونوں  
 طرف سے ہو رہا ہے + کہیں پاکستان  
 سے ہے - کہیں چین سے ہے + شاید  
 دونوں سے ہے + تو میں کہتا ہوں  
 کہ ہوشیار رہنا چاہئے - یا ادب + یا  
 ملاحظہ + ہوشیار - یہ بات نہیں کہ  
 ہم کمونسٹوں کو یہ سمجھیں کہ  
 ہمارے لوگ سب اس خیال کے ہو  
 رہے ہیں - ان کی نیت کے بارے  
 میں - مجھے معاف کیجئے +  
 مسٹر بھوپنہش کیٹا - مجھے یہاں  
 اردو کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے -  
 ہم تو قریب ہیں علم تم کو بھی لے  
 قبولیت -

یہ مسٹر بھوپنہش کیٹا کی ذہانت  
 ہے کہ کمونسٹوں کو گرفتار کرنے پر  
 ہم کہیں آپ کو گرفتار نہ کر  
 بیٹھیں - یہ تو مسئلہ مخالفین کا  
 مفروضہ ہے - آج ہندوستان کی جو  
 نازک پوزیشن ہے اس کی اہمیت  
 کو دیکھتے ہوئے اس طرح کے قانون

کی ضرورت ہے - یہ نہیں کہ سب  
 کمیشن یا فرقہ وارانہ فسادات یہ ہم  
 کو کہیں بھروسہ ہو سکتا ہے - اگر  
 خدا نخواستہ کہیں سب کمیشن ہو  
 جائے تو اس کے بعد کیا فائدہ ہو سکتا  
 آپ تلاش کریں گے؟ آگ لگنے پر  
 کوئی کلوں نہیں کیونتا ہے اس  
 کو پہلے سے تیار رکھئے اور اسی لئے  
 ایمرجلس کی ہم کو ضرورت پڑتی  
 ہے -

کس کو خبر تھی کہ اس سال  
 جنوری اور فروری کے مہینے میں  
 حضرت بل کا انسپیکٹ ہوگا -  
 میں سمجھتا تھا کہ مبارک  
 باد دیتا ہوں جنہوں نے دواجوہر  
 احتمال انگیز ہلکاسوں کے صرف  
 مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو + سکھ +  
 بودھ + عیسائی سب کے سب لوگوں  
 نے بڑے اتفاق و اتحاد کے ساتھ سیکولرزم  
 کی آواز کو بلند کیا اور اسلام کی  
 شان کو اس کے بنیادی پیغام امن  
 کو بحال رکھا اور کہیں فتنہ و فساد  
 کے لئے موقعہ نہیں دیا - ہم کو  
 بھی چاہئے کہ اس ملک میں  
 اس بڑے دیہے میں مختلف  
 صوبہ جات میں بھی نمونہ ہم بحال  
 رکھیں - چاہے ہندوؤں کی ہزار  
 کوششوں کہیں نہ ہوں مگر اہل  
 کشمیر کی طرح ہماری ایکٹا میں  
 فرقہ نہ آئے - ہو سکتا ہے کہ ہندوؤں  
 کی نیت بھی ہو کہ ہمارے آپس

میں فتنہ و فساد ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگوں کی بھی یہی نہت ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سب نردوش ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے ہندو بھی ہوں، بہت سے ایسے بودھ بھی ہوں اور بہت سے ایسے عیسائی بھی ہوں جن کے دل میں ہندوستان کی مسکھت کا وہ جذبہ نہ ہو جو ہونا چاہئے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں ہوں کہ ہر ایک کو مذہب کی بنا پر وہم و گمان کا شکار بنایا جائے اور انسان انسان پر پل پڑے اور اپنے گھر کو آپ گمزور کرے۔ یاد رکھو۔

خدا رحم کرتا نہیں اس بھر پر۔ نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر۔ یہ تو ایک طوفان بدتمیزی ہے۔ کیا یہی طریقہ ہے جس سے سروے پڑھے گی؟ یہ انسان کا کام نہیں ہے بلکہ شیطان کا کام ہے کہ فتنہ و فساد کو اُگے بڑھاتے جائیں۔ اور کہیں ایسا نہ ہو:۔

دل کے پہچھولے جل آئے سچے کے دماغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے

"Give the dog a bad name and kill it". That is not going to meet the ends of the situation.

یہ شیطان کا راز عمل ہے۔ مسٹر باجپئی اور مسٹر بھوپیش کہتا کی تقریروں کو سلیے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ رائے ہے کہ ایمرجھلسی نہ دے۔ یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا۔

مگر میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے گریہاں میں منہ ڈال کر دیکھیں اور ذرا ہندوستان کی فکر اپنے دل میں بٹھا کر دیکھیں تو وہ جو سچے ہوں گے اور جو مانتے ہوں گے وہ یہ ہے کہ ہندوستان آج خطرہ میں پڑا ہے اور ہم سب کو یہ کہنا چاہئے کہ اور بھی ہم قربانی کرنے کو تیار ہیں۔ آزادی کا معنی رکھتی ہے۔ آزادی کا خاک معنی رکھتی ہے جب یہ آزادی آہ و زاری کی صورت اختیار کرے۔ تو جب ہم دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہیں تو ہمیں اس آواز پر لبیک کہنا چاہئے کہ اور بھی زیادہ طاقتوں گورنمنٹ کو دی جائیں تاکہ گورنمنٹ اس ملک کو دشمنوں سے بچا دے اور آپ ہم تھلنے والے دل سے سوچیں کہ یہ آزادی؟ یہ جمہوریت؟ یہ سہول لہرتی کس طرح بحال رہے۔ یاد رہے کہ اتفاقی میں طاقت ہے اور نہ میں طاقت ہے۔ اس لئے ایک دھو اور ایک اور ایمرجھلسی میں ملک کی حفاظت کے لئے دن رات ایک کر کے تیار رہو، خدا حامی و ناصر ہے۔

نصف پل کے گوانا تو سب کو آتا ہے۔ مزا تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سالی۔

ہندوستان زندہ باد۔

†[श्री एन० एम० अनवर : मैडम डिप्टी चियरमैन, मि० श्री मुहम्मद तारिक की उर्दू तकरीर के बाद मैं ने यकायक सोचा कि मैं मद्रासी हूँ मगर मुझे भी यह ब्वाहिश है कि उर्दू जैसी प्यारी और मुश्तरका जवान में जो बतने अजीब की कोमी यकजेहती की शान है उसी जवान में तकरीर करूँ। आप जानते हैं कि मद्रास से हूँ जो काश्मीर से कोई दो

†[ ] Hindi transliteration.

[श्री एन० एम० अनवर]

हजार मील दूर जुनूब में है और उर्दू से मेरा रिश्ता वही है जैसा कि :

हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे,  
कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे ।

मुझे अपने मुहतरिम दोस्त मि० भूपेश गुप्त की काबलीयत का बड़ा एहताराम है और उनकी इन्टिमिटी के मुतल्लिक मैं हमेशा वही समझता आया हूँ कि शायद ही कोई उनसे बेहतर कम्युनिस्ट हो । बावजूद इसके एक बात उनकी मुझे समझ में नहीं आ रही है । उनकी तकरीर को मैंने बड़े गौर से सुना लेकिन अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि :

मह तकरीर का वक्त नहीं यह तदबीर  
का वक्त है ।

मह जोश का वक्त नहीं यह होश का  
वक्त है ।

मुल्क में अब क्या हालत गुजर रही है । उन्होंने बहुत से अखबारों का हवाला दिया, कभी "टाइम्स आफ इंडिया" के एडीटोरियल का हवाला दिया, कभी "स्टेट्समैन" की तरफ तवज्जो दिलाई । "We are now sitting on the edge of a volcano. लेकिन ये बातें माजी की हो चुकी हैं जो अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर की बातें थीं । लेकिन आज जिस वक्त हम इस मार्च के महीने में इस मुल्क की हालतों पर नजर डालते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि गोया हम एक कोहे आतिश फिशां पर बैठे हुए हैं । तो फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मि० भूपेश गुप्ता में यह जुरअत कैसे पैदा हुई कि वो यह कहें कि हमें एमरजेंसी की अब क्या जरूरत है । जरा मुलाहिजा फरमाइये उनका रेडिओलूशन जिसमें आप कहते हैं — "This house is of opinion that having regard to the improved situation in the country the state of emergency should now be ended." आप के दिमाग को क्या हुआ है । उसको

किसने कहा कि सिचुएशन हमारी इम्प्रूव हो चुकी है । मैं नहीं समझता कि कोई आकिल या दानिशमन्द इस सूरते हाल को इम्प्रूवमेंट कहेगा । सारी दुनिया जानती है कि करीब में जो मुलाकातें हुई, प्रैजिडेंट अयूब खां की और मि० चाऊ-एन-लाई की, इन मुलाकातों के बाद भी हमारे पास यह एहसास नहीं कि हालतें हमारे मुल्क की बहुत ही बिगड़ती जा रही हैं ।

मुझे बहुत ही सदमा हो रहा है कि मेरे प्यारे दोस्त मि० वाजपेयी लीडर जनसंघ को क्या हुआ । शायर ने क्या खूब कहा—

दिले नादां तुझे हुआ क्या है,

आखिर इस दर्द की दवा क्या है ?

वह भी इसी ख्याल के हैं कि हमारे यहाँ इस वक्त ऐमर्जेंसी की जरूरत नहीं है । मुझे बहुत ही दुख हो रहा है और हकीकत यह है कि—हक तो यह है कि हक अदा न हुआ । उन्होंने जो जो बातें यहाँ पेश कीं मैं मानता हूँ कि सिविल लिबर्टीज के हम अलम-बरदार हैं और जम्हूरियत के अलम-बरदार होने की हेतियत से हमारे मोहतरिम बुजुर्ग पी० एन० सभू को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि सिविल लिबर्टीज की जहाँ तक हो सके हम जरूरत से ज्यादा हिफाजत करें । शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ ऐसा बेहतरीन एक्सपेरिमेंट किया जा रहा हो जम्हूरियत का जैसा कि हमारे यहाँ ४५ करोड़ अशख्वास कर रहे हैं । हमने मुकम्मिल आजादी दी है । जरा गौर से आप अखबारों का मुतालिया फरमाइए, खुसूसन वो अखबार जो अपनी अपनी मकामी जवान में घाया होते हैं । कभी हिन्दी में, कभी उर्दू में । कभी गौर फरमाया कि कितनी ऐसी इस्त-अल-अंगेज बातें उनमें लिखी जाती हैं, कितनी फितना व फसाद की बातें लिखी जाती हैं । कभी किसी के केरैक्टर का एसे-सीनेशन होता है चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे वो कुछ हो । जब अपोजीशन वाले इस किस्म की हुकूमत की अदावत में, हुकूमत की मुख़ा-

लफ़्त में ऐसे ऐसे जज़बात उभारते हैं जिससे फ़सादात होते हैं तो क्या आप यह समझते हैं कि हुकूमत तमाशा देखती रहे और कोई कार्यवाही उन पर न करे।

मैडम डिप्टी चैयरमैन, मैं तो कहता हूँ और मेरा तो दावा है कि हुकूमत ने बराबर तौर पर इनतज़ामी कार्यवाही नहीं की। कलकत्ता के हादिसा से मैं यही कहूँगा कि ऐसे अख़बार जिनका रात-दिन यही पेशा है कि मुख़्तलिफ़ कौमों के दरम्यान फ़ितना व फ़साद पैदा करें, हर एक के ईमान पर, हर एक की मुहब्बत पर, हर एक की बफ़ादारी पर बदगुमानी की जाये। आखिर इस फ़ितने और इस ज़हर की हद क्या है। हम आपसे दरयाफ़त करना चाहते हैं। मैं यह सोच रहा हूँ कि जब मैं हिन्दुस्तान के इस मौजूदा नाज़ुक दौर का जिक़र करता हूँ तो कभी कलेजा मुंह को आता है कि हमारी हालत आगे चलकर क्या से क्या बदलेगी। जो हालत इस साल जनवरी में थी वो फ़रवरी में कहां से कहां तक बिगड़ गयी इस महीने मार्च को जब हम देखते हैं तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस मार्च महीने में आफ़त और बढ़ेगी या कम होगी। अगर किसी से पूछा जाये— और आप जानते हैं कि शहर के अमनो अमान के लिये हर जगह फायर ब्रिगेड रखे जाते हैं। फायर इंजन का होना ज़रूरी है गो उसके माने ये नहीं कि हर लम्हे फ़ितने फ़ितने फ़साद होते हैं—कहीं आन की आन में आग लग जाए तब इस फायर इंजन की ज़रूरत होती है या नहीं? अगर हमने एमरजेंसी को स्टेचूट बुक में रख दिया है तो इससे हमको बहुत कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है और कुर्बानी के बग़ैर हम आजादी को बहाल नहीं रख सकते हैं लेकिन यहां किसी इन्फ़ादी और किसी पार्टी या ग्रुप की अहमियत नहीं है। जैसा कि हमारे मुहतरिम दोस्त तारिक साहब ने बड़ी खूबी से ब्यान फरमाया, यह जो सवाल है यह हमारे देश का सवाल

3 RS-4.

है, इस मुल्क के अमनो अमान का सवाल है। मुल्क की सलामती का सवाल है। क्योंकि आज मुल्क ख़तरे में है। ज़हनूम है हमारी ज़िन्दगी जबकि यह मुल्क आफ़त में है, चारों तरफ़ से आफ़त ही आफ़त है। दुनिया की बहुत सी ताकतें मुख़्तलिफ़ तरीकों से इसके चारों तरफ़ जमा हो रही हैं और न जाने आगे चल कर हिन्दुस्तान की अजीमो-शान जम्हूरियत पर क्या हमला होने वाला है। बहुत सी बातें हर जगह सुनते आते हैं कि मुख़्तलिफ़ मुमालक के जो अख़बार हैं उनमें यह लिखा जाता है कि हिन्दुस्तान इतना बड़ा देश है और हिन्दुस्तान की मुख़्तलिफ़ कौमों का इस कदर मिलजुल कर रहना यह भी किसी की आंखों में खटकता है। हो सकता है कि पाकिस्तान के इस मौके पर यही सबसे बड़ा तारीख़ी मंज़र पेशे-नज़र हो कि हिन्दुस्तान में मुख़्तलिफ़ कौमों, इतने इत्फ़ाक़ व इत्तहाद से... (Interruption) कल और आज की बात छोड़िए। सकयूलरिज़्म—यह तो पन्द्रह साल का पीछा है। यहाँ हिन्दू धर्म की बज़ह से पांच हजार वर्ष से मुख़्तलिफ़ कौमों मिलती जुलती आ रही हैं और यह हमारा सिपिर-चुअल हरीटेज है जो कि दुनिया के लिए एक नमूना है। योरुप में बेशक ईसाई मज़हब के लोग हैं लेकिन सिर्फ़ एक मज़हब और एक कल्चर के। उनका लिबास एक है, उनकी आदतें एक हैं, उनके खाने-पीने का ढंग एक है बल्कि उनकी तर्जें ज़िन्दगी सब एक हैं, लेकिन ज़बान का तकाज़ा है कि योरुप में इतनी ज़बान की दीवारें खड़ी हैं यानि इतनी कौमों हैं, कोई जर्मन हैं, कोई फ्रेंच हैं, कोई स्विस् हैं, कोई ब्रिटिश, कोई डच, कोई स्वीड हैं, कई कौमों हैं, मज़हब इसलिए कि उनकी ज़बान का तकाज़ा है। बावजूद इसके कि हमारे मुल्क में १५-१६ ज़बानें हैं, बावजूद इसके कि हमारे मुल्क में १० या १२ कौमों हैं, बावजूद इसके कि हमारा तर्जें ज़िन्दगी ज़नूब में एक तरीके का है और शमाल में कई तरीके का है, बावजूद इसके कि हमारे बाहमी रस्मो-रीत, खाना-पीना,



[श्री एन० एम० अनवर]

रहन-सहन, कहीं-कहीं जुदा है, बावजूद इन तमाम तफर्रूक़ात के एक करिष्मा है, एक मुअज्जा है, यह दुनिया के लिए एक नमूना है कि हिन्दुस्तान एक खूबसूरत ज़मिनस्तान है जिसमें रंग रंग के फूल हैं।

सारे जहाँ से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलियाँ हमारा भजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम वतन है हिन्दुस्तान हमारा

यह नमूना दुनिया के किसी मुल्क ने पेश नहीं किया। योरोप और अमरीका के लोग जो हमें सबक देते हैं सलामती का, इत्तफ़ाक़ का, इत्तहाद का, क्या उनके यहाँ इस तरह के मसले नहीं होते? अमरीका में ग़ोरे और काले लोग जो मुक़्तसिर तादाद में हैं लेकिन इस कदर वहाँ रेशियल कौम्प्लेक्स के मामले होते हैं बावजूद इसके कि कान्स्टीट्यूशन में हुकूमत ने मुसावात कर रखी है। साउथ अफ्रीका जिसकी बदतमीजी का दुनिया को इल्म है अब वो हमें सबक देने आया है—

काबा किस मुंह से जाओगे गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती ॥

यह हिन्दुस्तानी है जो सारी दुनिया को इल्मो-अदब का सबक देते आये हैं। यह वो हिन्दुस्तान है जिसने सारी दुनिया को अम्नो-अमान का सबक दिया। यह वो हिन्दुस्तान है जो दुनिया को इत्तफ़ाक़ वा इत्तहाद का नमूना हजार वर्ष से देता आ रहा है। यह कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबक नहीं है सक्कूलारिज्म का, यह ऐसा महील है जिसे हमारी सर जमीन में हमारे आबा-व-अजदाद ने बहाल रखा। मुबारक है आफरीन, आफरीन, आफरीन—

सबक पढ़ फिर सदाकत का,  
शुजाअत का, अदालत का;  
लिया जायेगा तुझ से काम,  
दुनिया की इमामत का ।

ऐसे एक समाज को जब खतरा दोनों तरफ से हो रहा है, कहीं पाकिस्तान से है, कहीं चीन से है, शायद दोनों से है, तो मैं कहता हूँ कि होशियार रहना चाहिए। बाअदब, बामुलाहजा, हाशियार। यह बात नहीं कि हम कम्युनिस्टों को यह समझें कि हमारे लोग सब इस ख्याल के हो रहे हैं—उनकी नीयत के बारे में—मुझे मुआफ़ कीजिये— मि० भूपेश गुप्ता—मुझे यहाँ उर्दू का एक भिसरा याद आ रहा है—

हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे।

यह मि० भूपेश गुप्ता की जहानियत है कि कम्युनिस्टों को गिरफ्तार करने पर हम कहीं आप को गिरफ्तार न कर बैठें। यह तो मसला मुखालफ़ान का मफ़ूजा है। आज हिन्दुस्तान की जो नाजुक पोज़ीशन है उसकी अहमियत को देखते हुए इस तरह के कानून की ज़रूरत है। यह नहीं कि सिविल कमीशन या फिक्वेयराना फसादात पे हमको कर्मा भरोसा हो सकता है। अगर खुदा-न-खास्ता कहीं सिविल कमोशन हो जाए तो उसके बाद क्या फायर ब्रिगेड आप तलाश करेंगे? धाग लगने पर कोई कुर्मा नहीं खोदता है, इसको पहले से ही तैयार रखिये और इसीलिए एमरजेंसी की हमको ज़रूरत पड़ती है।

किसको खबर थी कि इस साल जनवरी और फरवरी के महीने में हज़रतबल का इंसोडेंट होगा। मैं हमेशा काश्मीरियों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने बावजूद इश्तख़ाल अंग्रेज हंगामों के सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिन्दु, सिख, बौद्ध, ईसाई सब के सब लोगों ने बड़े इत्तफ़ाक़ व इत्तहाद के साथ सक्कूलारिज्म की आवाज़ को बलन्द किया और इस्लाम की शान को, उसके बुनियादी पैग़ाम अमन को बहाल रखा और कहीं फितना व फसाद के लिए मौका नहीं दिया। हमको भी चाहिये

कि इस मुल्क में, इस बड़े देश में, मुस्लिमिफ सूबाजात में यही नमूना हम बहाल रखें चाहे दुश्मनों की हजार कोशिशें क्यों न हों मगर अहले काश्मीर की तरह हमारी एकता में फर्क न आए। हो सकता है कि दुश्मनों की नीयत यही हो कि हमारे आपस में फितना व फिसाद हों और यह भी हो सकता है कि मुस्लिम लोगों को भी यही नयित हो। मैं यह नहीं कहता कि हम सब निर्दोष हैं। हो सकता है कि बहुत से ऐसे हिन्दू भी हों, बहुत से ऐसे मुसलमान भी हों, बहुत से ऐसे बौद्ध भी हों और बहुत से ऐसे ईसाई भी हों जिनके दिल में हिन्दुस्तान की मुहब्बत का बह जजबा न हो जो होना चाहिए। मगर इसके ये माने नहीं हैं कि हर एक को मजहब की बिना पर वहम व गुमान का शिफार बनाया जाये। और इन्सान इन्सान पर पिल पड़े और अपने घर को आप कमजोर करें। याद रखो—

खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर  
न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर।

यह तो एक तुफाने-बदतमीजी है। क्या यही तरीका है जिससे मरवत बढेंगे। यह इन्सान का काम नहीं है बल्कि शैतान का काम है कि फितना व फसाद को आम बढाते जायें और कहीं ऐसा न हो—

दिल के फफाले जल उठे सीने के दाग से  
इस घर को आग लग गयी घर के चिराग से।

"Give the dog a bad name and kill it". That is not going to meet the ends of the situation.

यह शैतान का राहे अमल है। मि० बाजपेयी और मि० भूपेश गुप्ता की तकरीरों को सुनने के बाद मैं यह समझता हूँ कि उनकी यह राय है कि एमरजेंसी न रहे—  
यह वो लफज कि शरमिन्दा-ए-मानी न हुआ—

मगर मैं कहता हूँ कि वो अपने गरवान में मुंह डाल कर देखें और जरा हिन्दुस्तान की फिक्र अपने दिल में बिठा कर देखें तो वो जो सुनते होंगे और जो मानते होंगे वो यह है कि हिन्दुस्तान आज खतरे में पड़ा है और हम सब को यह कहना चाहिए कि और भी हम कुर्बानी करने को तैयार हैं। आजादी क्या माने रखती है? आजादी क्या खर माने रखती है जब यह आजादी आहोजारी का सुरत अस्तियार करे। तो जब हम दुश्मनों का मुकाबला करते हैं तो हमें इस आवाज पर लम्बेक कहना चाहिए कि और भी ज्यादा ताकत गवर्नमेंट को दी जाये ताकि गवर्नमेंट इस मुल्क का दुश्मनों से निजात दिलाये और आप हम ठंडे दिल से सोचें कि यह आजादी, यह जम्हूरियत, यह सिविल लिबर्टी किस तरह बहाल रहे। याद रहे कि अलफाक में ताकत है और नफाक में हलाकत है, इसलिए एक रहो और नेक रहो और एमरजेंसी में मुल्क की डिफाजत के लिए दिन रात एक करके तैयार रहो। खुदा हमो व नासिर है।

नशा पिला के गिराना तो सबको आता है  
मजा तो जब है कि गिरती को थाम ले सकी।

[हिन्दुस्तान जिन्दाबाद।]

SHRI KRISHAN DUTT (Jammu AND Kashmir): Madam Deputy Chairman, I rise to oppose the Resolution sponsored by my hon. friend, Shri Bhupesh Gupta. I am really at a loss to understand how such a wide awake and experienced politician as Shri Bhupesh Gupta could sponsore such a Resolution at the present phase of Indian history. My feeling is, that he has been motivated more by the anguish that he has felt at the arrest of his communist comrades. Instead of finding a remedy in some other direction for getting them released he has adopted a course of such a sweeping nature that it really cuts at the very roots of India's freedom and India's security. Instead of advising his friends to feel the gravity of the

[Shri Krishan Dutt]

situation obtaining in the country, asking them to fall in line with the other patriotic elements who are doing their best to strengthen the defence preparedness of the country, to strengthen the hands of the Government to meet any eventuality that the country may be called upon to meet at the borders, to give at this time an idea to people outside that there is now no reason left or that circumstances have so changed that the country does not need the state of emergency, is, I think, not doing any service to the country. No hon. Member, no patriotic Indian can say that the danger on the borders has lessened in any degree. On the contrary, keeping in view the reports in the press and the thickening relations between Mr. Ayub and Mr. Chou-en-lai, they are a pointer to a different conclusion. I feel that in the near future circumstances are going to shape themselves in a manner which will increase the danger to India. I am one with Mr. Anwar in feeling that the greatest discomfort and the greatest provocation which Pakistan is getting from India is our communal harmony, our secularism, our peaceful approach and our peaceful progress. This is not being tolerated at all by Pakistan. India is living in perpetual frustration of Pakistan's ideology or refutation of Pakistan's ideology. That is the greatest headache and the greatest frustration that Pakistan is feeling. Pakistani rulers are feeling in their hearts that unless and until India is also faced with some internal conflagration on the basis of a Hindu-Muslim conflict, the very basis or justification of Pakistan will disappear. If the present progress, communal harmony and peace continue in India, that is the worst condemnation of Pakistan that can be imagined. Therefore, Pakistan wants that somehow or other India must be put in a position where it can justify the two-nation theory. Therefore, my reading is that Pakistan is going to manoeuvre events, is going to engineer events, which will create communal tension inside the country

and will give added force to those elements which can work and which are even now working as a fifth column for Pakistan's aggression. Kashmir is not an end in itself for Pakistan. It is a means for the destruction of India's secular democracy. Pakistan wants to use Kashmir to enforce its domination on the whole of India. I think hon. Members will be surprised at what I say, but the ideology or the mentality of Kasim Rizvi is still in the minds of the rulers of Pakistan. The Muslim Leaguers have this basic idea in their mind that India's Government was taken over by the British from the Muslims and it is the Muslims who are entitled to rule Delhi after the withdrawal of the British. That is the idea which is ruling the minds of Pakistani rulers from the very start and inception of Pakistan. To keep up their theory there are persistent and constant efforts of the Pakistani rulers going on. Otherwise we cannot make out the motive behind the persistent refusal of the Ayub regime to the most natural and most sincere offer of our Government for a no-war declaration between India and Pakistan. What is behind their minds? Why don't they accept this straightforward offer? Why don't they wish that there should be eternal peace between India and Pakistan and inside India and inside Pakistan also? Therefore, connect this with that mentality of ruling Delhi just as Kasim Rizvi used to tell that he will just put the League flag on the Red Fort. That is the basic reason for Pakistan to continue its intransigence.

Now let me take the other side, China. Red China's rulers are militant Communists who want international Communist domination as far as possible on the surface of this earth—Communist imperialism of the Chinese variety, that is what I am referring to. By their massive invasion of 1962 they have grabbed more territory. They have strengthened their position all the more. They have got up-to-date roads, godowns and all

sorts of war arsenal and cantonments. Now they are in a very favourable position to advance further. Now add to this the most dishonest tactics! which Mr. Ch'ou-En-lai is practising, his collusion with Mr. Ayub Khan. This is a collusion between two aggressors. Both are now combining; to grab as much of Indian territory by joint action as they can. Just as there are communalists who can be used as fifth columnists by the Pakistan rulers, there are also pro-Peking Communists here who can be used as agents for internal subversion against the Government of India and the Indian people to subvert our democracy, to subvert our freedom.

SHRI BHUPESH GUPTA: We have always repudiated that charge and suggestion. Up till now they have not been proved.

SHRI KRISHAN DUTT: As a party you may have done it. That is quite correct. But I am talking of individuals.

SHRI BHUPESH GUPTA: We have been in the last fourteen months asking Government to produce a shred of evidence against anybody. It is no question of resolution.

SHRI KRISHAN DUTT: That resolution also was not unanimous?

SHRI BHUPESH GUPTA: Why are you repeating a fourteen-month old allegation which is false, malicious and perverse?

SHRI KRISHAN DUTT: I have mentioned all this background with the sole object of stressing that the danger to Indian freedom and Indian integrity is increasing day by day. On the continuance of the emergency there can be no two opinions. With regard to the arrests and the misuse of the powers under the Defence of India Rules, that is a separate question altogether. The right use or the wrong use of the powers is not a determining factor either for the revocation or the retention of the

emergency. The real factor that determines the fate of this resolution is the intensity of the state of danger in which we are at present placed with regard to our neighbours, north, east and west. I hope and I am confident that the hon. Members here and even the people outside are fully conversant with the seriousness of the situation in which our country is at present.

I may again refer to the example of the fire brigade used by my hon. friend Mr. Anwar. At present there is no actual firing going on on the borders. That is quite correct. But should we have the fire brigade only when the conflagration is on and the flames are shooting to the skies? The flames may have been quenched but the smouldering fire would be still there, and we cannot tell the fire brigade to pack up and go away just because the flames have been quenched. But when the smouldering fire is still there, we must keep the fire brigade on the spot till it is totally extinguished.

SHRI BHUPESH GUPTA: You keep the fire brigade in the depot.

SHRI KRISHAN DUTT: Not in the depot. Fires are smouldering on the border.

SHRI BHUPESH GUPTA: I am not asking you to demolish the fire brigade. Keep it in the depot. Likewise keep the emergency in the Constitution.

SHRI KRISHAN DUTT: It must be kept in action. Now the greatest task before the country at the present moment is preparing for defence, and not only for defence, we have to take back the territory from the Chinese illegal occupation. We are pledged to that. There is a sacred resolution of this hon. House on that point, and the time is fast coming when India will be compelled by the intransigence of the Chinese to take positive action there. For that positive action we

[Shri Krishan Dutt]  
are going to prepare and prepare most  
valiantly and determinedly. Thank  
you.

श्री गोपीकृष्ण बिजयवर्गीय : उपसभापति महोदया, मैं श्री भूपेश गुप्त के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जो दलीलें श्री भूपेश गुप्त ने दी हैं वे गलत हैं और कोई भी उनसे संतुष्ट नहीं है। एक तो आपने यह कहा कि चीन वापस चला गया है, सोज फायर लाइन कान्सालिडेट हो चुका है और अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन खतरे को कम समझना, यह बिल्कुल ही गलत बात होगी। चीनी लोग जहाँ वे वहाँ और ज्यादा मजबूती से गढ़े हुए हैं। वे जमे हुए हैं और उन्होंने अपनी फौजें और ज्यादा कर दी हैं, हथियार बढ़ा लिये हैं, बहुत से हवाई अड्डे वगैरह बनाए हैं। तो वे पूरी तरह से अपनी जगह पर हैं और ज्यादा मजबूती से जमे हुए हैं।

फिर इसके अलावा पाकिस्तान भी इन दिनों हिन्दुस्तान के खिलाफ हो रहा है और जगह जगह ऐसी घटनाएँ होती हैं कि वह हमारे मुल्क में आकर हमारे सिपाहियों को मार जाते हैं, हमला कर जाते हैं और दूसरी तरह से उनकी तैयारियाँ हैं। पाकिस्तान और चीन की फौजें भी हमारी सोमा पर बराबर लगी हैं। इसका मतलब यह है कि खतरा कम नहीं है बल्कि खतरा ज्यादा है। दूसरे, इस बात को मान लेना कि खतरा कम हो गया है, चीन का सोज फायर एक तरह से कान्सालिडेट हो गया है, हम इस खतरे को, हमले को हल्का समझते हैं, या एक तरह से अगर हम चीन की सद्भावना समझ कर विश्वास कर लेते हैं तो एक बहुत गलत दलील को मान लेते हैं। दूसरे विरोधी पार्टी के एक सदस्य श्री वाजपेयी जी ने इस दृष्टि से कहा कि मैं यह नहीं कहता कि खतरा कम हो गया है, हमले को मैं हल्का नहीं समझता हूँ लेकिन

पावर्स का मिसवूज हुआ है, दफ्तरों ने कुछ गलतियाँ की हैं और फिजूलखर्ची हुई है, इसलिए मैं इस विवाद का स्वागत करता हूँ ऐसा श्री वाजपेयी जी का कहना है। उनकी यह दलील भी कि किसी अफसर ने गलती की हो या किसी अफसर ने इस कानून का दुरुपयोग किया है, मैं इस दलील को भी नहीं मानता हूँ। जब देश को और ज्यादा खतरे का सामना करना है तो ऐसे समय में जो देश के पास सब से बड़ा हथियार कानून का है उसे हमें रद्द नहीं करना चाहिये। हमें यह नहीं समझना चाहिये कि गवर्नमेंट के किसी अफसर ने, गवर्नमेंट के किसी मिनिस्टर ने या किसी राजदूत ने कहीं कोई गलती की हो तो हमें इस हथियार को छोड़ देना चाहिये। प्रसंग में जब देश में एमरजेंसी है तो हमें सबको ज्यादा काम करना चाहिए। एक दलील यह भी दी गई है कि सोमा से १०० मील तक इस एमरजेंसी को लागू किया जाय और बाकी देश से इसको हटा लिया जाय। इसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह एक अव्यवहारिक बात है। इस समय सारे देश में एमरजेंसी रखना चाहिए और सब पार्टियों को देश की हिफाजत में गवर्नमेंट का साथ देना चाहिये। हर पार्टी को अपनी अलग अलग खिचड़ी नहीं पकानी चाहिये।

अभी हमारे होम मिनिस्टर साहब श्री नन्दाजी ने अपने भाषण में बतलाया कि एमरजेंसी का बहुत व्यापक रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया है और बहुत ही कम मामलों में इसका इस्तेमाल किया गया है और न कानून का दुरुपयोग ही हुआ है। उन्होंने आंकड़े दे कर तलाया कि बहुत ही कम कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन कुछ दूसरे लोगों को, मसलन कुछ व्यापारी हैं, कुछ आप लोग हैं जिन्होंने गलत काक किये हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसलिए श्री भूपेश गुप्त जो यह कहते हैं कि एमरजेंसी को हटा देना चाहिये वह यह बात सिर्फ अपने

कुछ साधियों को छड़वाने के लिए कहते हैं। अगर इस बड़े हथियार को वे सरकार से हटवाना चाहते हैं तो इससे देश को बहुत नुकसान हो जायेगा। मैं ज्यादा न कह कर सिर्फ यही कहूंगा हमारे देश की इस समय जो हालत है उसको देखते हुये यही कहा जा सकता है कि इस समय हमारे देश के ऊपर खतरा बढ़ गया है। इस कानून के मिसयूज होने और कुछ गलतियाँ के बारे में ज़ा बात कहा गई है उससे यह साबित नहीं होता है कि देश की ऐसी परिस्थिति हो गई है जिससे हम इमरजेंसी को हटा दें। इसलिए इस दृष्टि से मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

KUMARI SHANTA VASISHT (Delhi): Madam Deputy Chairman, I rise to oppose the Resolution of Mr. Bhupesh Gupta seeking that the emergency may be ended. I think the danger to the country which started with the invasion of the Chinese of this\* country has not ended. The threat from Pakistan to India has not ended. As a matter of fact, all through this period, for more than one or one and a half years, on various occasions and at various times, there was much fear and anxiety that some attack might come from China during the winter period or that some trouble might take place on the Pakistan border, and those fears were there almost constantly all through this period. Therefore, there is no occasion to feel that the emergency could be ended or to feel that there was no danger to the country's security or that there is no internal danger or external danger. The emergency was declared and the country become mobilised for preparation and work to meet the aggression. But there have been various factors and trends which have not been very happy. Government declared the emergency which was very, very necessary; it had to declare an emergency. Even before it was declared, the moment the Chinese aggression came. I felt that a state of emergency should be declared, and a few days

after that, it was declared. Now the trouble from them continues.

Personally I would say that the Government has not taken as strong an action against the various people, the various elements and the various trends as they should have done to meet the situation. If it is an emergency, then it means that we should prepare the country for defence and make other preparations; not in the next 20 years but in the next three years we should complete the entire programme of defence and other preparation; we should not spread it over so many years as could be done normally or even as it is done today. I am very radical in this, and I do feel that to take this work easy and to go along about it is not going to help the situation. I fully appreciate that the Government is doing its utmost to make the various preparations to increase production, to increase the number of the fighting forces in the various units and so on and much work is being done, much of which is personally known to me also. All this work is being done and I do appreciate that the Government is doing everything to increase our preparedness, military preparedness and so on. But I must say that even that does not seem to go far enough; that is not enough as far as our preparations and our handling of the present situation are concerned. It is important to quicken the pace even further. I could quote even a large number of examples here to show that the Government machinery does not seem to function as fast and as promptly as it should. There may be—and I am sure that there are—many Ministers working very hard, overworking, hardworking, with serious concern and deeply distressed over the state of affairs and anxious to meet the state of affairs. There seem to be quite a few officers also who are anxious and worried and who work very hard. But apart from these very small sections of the people—that means the large number of Ministers and a few officials—it seems to me that by and

[Kumari Shanta Vasisht.] large, the bureaucratic machinery could not care less as to what is happening in the country. This is my impression from the various offices, from various people.

And another factor is that we are very little conscious of the military preparations, as to how they are or they should be. Whenever the question comes up that the military authorities should be given the necessary sanction, it takes months and months. Nobody bothers to give these sanctions. That applies to the various departments and the Ministries. When the land is wanted by the Cantonment Board, every single member of the Board seems to be so unconcerned and so indifferent as to feel why the Board, the Contonment Board, should want some more land for the anton-ment area. We have no desire to give land to the Cantonment Board whereas we are very anxious to give land for a cinema house or for a luxury hotel because the Tourist Department wants it. It is more concerned about the tourists, half the number of whom may come for intelligence work. The officials do not seem to have half as much concern for their own country's preparations. These are the examples with which even I personally come in contact. Those very members of the Boards and the Committees are more anxious to have hotels and cinemas and shopping areas and commercial areas and increase the prices of land by declaring it. to be a commercial area or an industrial area, etc. But there is no consciousness, there is no feeling, there is no understanding that military areas are more important, that military facilities should be given to them 'or that these are more important than all these cinema houses and hotels. In the Master Plan various parts are marked as defence area; all those have been beautifully marked in the Master Plan of Delhi, and every single patch which is supposed to be used by the Defence Department or by the mihitary authorities is marked there. And the Master Plan is sent to America so that

they can appreciate what a beautiful Master Plan we have prepared. Whe ther we will implement it or not is another matter. But that Plan with all the marking, etc. is given out to them because we have no concern at all that many things in this country must be kept secret. Our planning must not become public property. The defence preparation of India is not meant for exhibition and publication abroad. But our planners, in their great joy and enthusiasm, our Government officials also in great pride and enthusiasm, feel that we must have a good certificate from the American planners. They do not realise that the country must function whether the American planners give them a certificate or not. That is not necessary. All your military areas or defence areas, here or anywhere else, whatever installations you have there, these are well known to everybody else. Here I would point out that when we had this emergency—and it is there—we have allowed so many foreign people, so many foreign correspondents and foreign people to go to every part of our country. They can go to the border areas; they can go to the trouble spots. Every single trouble spot in India, in the last few years, has been visited by a large number of foreign people; whether we can go there or not does not matter; whether we are given any facilities to see our areas, is not necessary. But every other foreigner, who wants to go into any part of India, and particularly the trouble spots on our borders, they are given all facilities and all sorts of help to go there which, I think, should never be allowed. The British people would never allow anybody to go to their own trouble spots. The Americans would never allow such a thing. The Russians would never allow such a thing. The Chinese would never allow such a thing. But we are casual and careless about our own state of affairs, and we think that India is the property of the whole world and we are their children to be patted by everybody in the world, and we do not bother that we should keep the

secrets of the Government, we should keep our military secrets, we should think of the security of the country. The foreigners come and they take photographs of all your Himalayan areas, through the plains and otherwise, and we do not bother to see that nobody should take photographs of all this terrain or that area, as if these were small matters.

Then sanctions are not generally given; I do not think the Defence Ministry, in its decency or good sense, or even its own self-respect, would publicise the fact that sanctions are not available to them. How can they say it? They would not say it; it would not help them very much either. But it is the responsibility of all the other Ministries, and the Government as such, to see that every little demand made by them, every single sanction asked for by them, should be promptly dealt with, within twenty-four hours. I am even aware that the wagons of the railways are not made available for military work. What are the wagons for? Why can't they be available for military purposes, and why can't they be given the priority?

And these military preparations and defence preparations should be their very first priority and the decisions should be taken, all decisions, at least a large number of decisions, should be taken within twenty-four hours or within two days. But they sit over the files for months and months and months. Nobody bothers about the decisions, and so on. Of course some Ministers, I am sure, must be sleepless, worrying about the country. But, by and large, the bureaucracy and the machinery do not care, and this is not the way to tackle serious problems of the country. I would more concretely say; though we have not had trouble directly with Pakistan so far, and China did not come back after they providentially went back, supposing there is an attack this spring, supposing there is an attack this summer, am I to understand that the Government is ready for it? I am sure they are not ready, and I am very sorry to say this. I understand their limita-

tions, but the fact remains that the machinery goes very slow and that they are not at all ready to face a situation of this kind. Of course, if that attack comes, everybody will become active all over again and the machinery will start going—no doubt there will be panic and fear—and again mobilisation of all our resources to meet the situation. But knowing full well that there are as many chances of an attack coming as there are of its not coming, we have not made the full preparations that were absolutely necessary. Another point I would say—which even in connection with the debate on the President's Address I had pointed out—that full co-operation must be given to the Defence Department and the Defence Ministry for their work, that work should be expedited and the requirement quickly tackled. I do not know\* how far the Government was bothered about it, but I hope they will do something.

Another thing is that prices have been rising tremendously. Though we have the Defence of India Rules and all sorts of other Rules in this emergency, prices have gone up like this, and the Government has not been able to check it. I am very happy to say that the Finance Minister has presented a very good, a very nice Budget; he has also felt it and is concerned about the rising prices. We are merely saying we are concerned and we are concerned and we will try not to let the prices go up, whereas they are going up all the time. By merely saying that you do not want the price\* to go up, the high prices now are not going to remain under any sort of check. Prices are going up, much to the dislike and resentment of the people at large. By and large the entire country feels the impact of these prices; they resent it and feel bad about it. But the Government has remained, unfortunately, somewhat indifferent and callous in this matter. They say they are concerned, but I have never seen them take any effective steps to check the rising prices. Perhaps the influence of the trading community or the business community



LKanwi'i Shanta Vasisht.J  
 is so mucn on Uiem that they do nol  
 Know what to ao, w/um tney shoula  
 uisplease and whom they should "ol  
 uisplease, miu it they touch, one sec  
 tion, tliat section will try to hit at  
 mose people as there are lots ot man-  
 eaters at large, and il' they try to irri-  
 tate some vested interests or the other,  
 I luyi appreciate and understand thai  
 these people will get into trouble. The  
 Ministry also will find various obsta-  
 cles ana troubles and pin-pricks. I  
 sympathise with them in their predic-  
 ament, whicli is their predicament as  
 well as our predicament. But this  
 situation has to be faced whether you  
 like it Ol not; these rising prices have  
 to be tackled. The resources may be  
 taken over, the distribution may be  
 taken over. How is it that the pro-  
 ducer gets nothing whereas the distri-  
 butors are practically making hundred  
 per cent profit even in foodgrain?, and  
 a shortage is created? And all this  
 is happening, but the Government is  
 not particularly taking any strong  
 action. By saying: "We shall take  
 action; we shall take action", they  
 will go on for, say, five years. And  
 so when shall you take action? But if  
 no action is taken now, this problem  
 will remain and it will recoil on the  
 Government, so that action is neces-  
 sary to meet the situation as it is to-  
 day. Even in the interests of the  
 Government and in the interests of  
 the business community, in the inter-  
 ests of the business people, it is neces-  
 sary to ease the situation, so that the  
 various sections of the people can live  
 in peace and be able to manage their  
 livelihood somehow. Otherwise, these  
 elements who are hard hit, will rise in  
 revolt against the well-to-do in the  
 society, against the moneyed people  
 of our country, against the business  
 people here, against the government  
 itself, they will feel a tremendous  
 amount of resentment, and the  
 resentment and various other  
 things will recoil, and that  
 will be against the interests of the Government  
 as well as the business people and the  
 moneyed people. Therefore, in the interests of  
 all these sections it is important to see that the

I prices do not rise—no matter what I  
 steps the Government have to take.

.Lastly I would again say one thing more  
 displeasing. I am in the habit of displeasing  
 various people, Ministers and various  
 sections of people. (interruptions) But I  
 hope they will appreciate what I am saying.  
 Now I wish to say a word about the press. the  
 press has also behaved sometimes nicely and  
 sometimes very badly. When the trouble  
 was on, that is, the Chinese attack came, then  
 they were co-operative, very helpful, and by  
 and large the Government got very good co-  
 operation while the trouble was going on.  
 But after that there are large numbers of  
 weeklies, and daily papers, and yellow  
 press and much rubbish is thrown before the  
 people—fed to the people—speaking  
 against everybody, beginning from the Prime  
 Minister, doing every type of damage that they  
 could do, to the Government, to the various  
 Ministries, to the Prime Minister, to the  
 Congress Party, to our programmes, to our  
 Plans, and everything. A whole spate of  
 materials is out, most irresponsible, some of  
 which are using their blackmailing and bul-  
 lying tactics. But the Government hav, not  
 bothered to take any action against them. If  
 this type of emergency was faced by any  
 other country, they would have banned at  
 least half a dozen papers they would have  
 taught a lesson to the others . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is time.

KUMARI SHANTA VASISHT: . . . and no  
 papers would have misbehaved as our papers  
 sometimes seem to misbehave, and they do  
 not spare anybody under the sun. It is God  
 probably who is left out by them. And the  
 press has sometime? behaved in a very  
 partisan spirit, with very great vengeance, with  
 an axe to grind, with selfish interests and  
 motives, and with very great unfairness—if I  
 may say so. Press is the fifth estate; they are  
 supposed to have a certain amount of  
 responsibility, a certain kind of responsibility.  
 We were hoping that they would behave with  
 responsibility. But

il tht- press people do not behave, it ii ior tne Government to see to it, to lake them to task, to ban those papers, not allow that much of pernicious oro-pagaiuia to be carried on against the Government as well as against the Ministers and against the Congress Party itself, and for the last so many years, two years or three years or even more, every day, there is a cartoon with a Gandhi cap. Today you are ridiculing the Gandhi cap. Some time, even these papers may have cause to regret what they are writing today, all the caricatures they are making, all the cartoons they are putting out. If any research scholar wants to sit down and study political situation today and make a collection, even for the study of political history, only of these cartoons, he will make out the picture of the rot that is reflected in these papers today, a rot that is reflected in the indifference of the Government, and the indifference of all of us when we see our Gandhi cap being ridiculed day after day after day, for years and years and years, and we are indifferent; we do not bother. At best you may criticise an action; you may criticise a programme or a policy or even certain individuals. But this Gandhi cap is being ridiculed for months and years, and the Government is not bothered. Why should these papers be allowed to ridicule the Gandhi cap? After all, these were the relations of the editors of these very papers who were responsible for these caps as ■■■ell as the Congress movement, the freedom movement, and they are today indifferent to the work don<; by their fathers and grand fathers, and they are now bringing a bad name to the Party, to the Government, to the Ministers, to even the great leaders of our country, who are great leaders not only in this country but in the entire world, who are respected. But our own people, very small people, ridicule our leaders. They make fun of them. They ridicule our Gandhi cap. They ridicule our Ministers. They show some Ministers sleeping, some Ministers doing some- I thing else. They show as if our

Ministers do not understand what is going on in the House and they do not know what they are speaking. If they do not know what to speak, how would they be here? They say everything they possibly can. Even a student doing some research would make out a sad picture of these papers. They condemn our own Government by saying very fantastic, crazy, highly mischievous things. I think it should be for the Government to put an end to this sort of mischievous behaviour of these papers. Let me say that these papers will some day regret what they have been doing because they undermine the national interests. Naturally, from the trends in the press I feel there is a mischievous propaganda going on all over against the Government in order to undermine it and the Government does not seem to bother about it. When all this trouble accumulates and the cumulative effect of it is felt after five or ten years, at that stage we will not be able to mend matters. Today these matters can be mended. They should be examined by the Government and something done about it before it is too late when we shall be only feeling sorry and shedding tears. That, then, would not be the time for us to put any corrective to these things. So today when we see these trends, when we see all these things, let us take action about it. Let us go about it in the spirit of the emergency that is there and show that we mean to tackle the task.

Thank you.

SHRI BHUPESH GUPTA: Madam Deputy Chairman, it is good that this subject has been discussed. It is not possible for me within the time at my disposal to answer every single point which has been sought to be made out by the Members opposite. The hon. Members opposite were, were, between themselves, sharing the orchestra played by the Home Minister. The music came but the tune was set by him. He played it. He set the tune as to whether the emergency should remain or not. I cannot expect, naturally, the hon. Members of the Congress Party to

[Shri Bhupesh Gupta.] support me openly. But Some of them indirectly have done so. Perhaps they are not conscious of the extent to which they have done so. But none the less they have done so.

I am very grateful to the hon. Members, Mr. Vajpayee, our friend, Mr. Dahyabhai Patel, and others who have supported this resolution—Mr. Gaure Murahari, Mr. Kureel and others including Mr. Mani. I counted 14 names of the hon. Members who have clearly supported the demand for ending the emergency.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: With reservation.

SHRI BHUPESH GUPTA: But you have not supported it, I know that. If I had taken free votes, I would have got this thing passed. It is quite clear. Now let me deal with the arguments. But I should like to concentrate on the arguments given by the Home Minister and by the Prime Minister. First of all, I would like to say that listening to these speeches I felt that we were facing something which I had never known. These speeches would stand in sharp contrast to what was said in November, 1962 when the Proclamation was being discussed in this House and the Home Minister spoke. If you read the speech of the then Home Minister, Shri Lal Bahadur, you would find that that speech stands in sharp contrast to what the hon. Home Minister said in support of it today, about the continuance of the emergency.

Madam, what was the case of Shri Shastri at that time? He was asking for emergency powers because the situation was grave indeed and the Proclamation said so. At that time the Chinese forces were advancing in huge numbers, as you know, into our territory. Today it is not so. Naturally there is a difference in the situation whatever else you may say. The thing which exercised the mind at that time was precisely the situation, when the Chinese forces were moving

and we had to deal with the situation in the sense of army movements and so on. It was at that time not a question of defence production or defence preparation as such. It was a question of moving the supplies quickly, moving the Armed Forces quickly, taking prompt action, without waiting for any kind of delays, procedural or administrative. Then there was justification. At that time also similar arguments were given. That was the substance of the arguments which called for, according to the Government, the emergency powers. And we gave the emergency powers, all of us. At that time we were all unanimous. Today there is division. Today you can see there is no unanimity over this matter. It may be that that side has more Votes. None the less there is division today. That also is an objective reflection of the situation that prevails in the country.

Madam, when Lal Bahadurji, came here the other day he asked us to think over the problem. He said the dispute was hanging fire indefinitely and some way should be found to solve it since we are dedicated to the cause of peace. Therefore, we should apply our mind to some peaceful solution of the problem. Earlier when Premier Khrushchev made the proposal to renounce war for settling territorial disputes, we supported it. And in that background the Minister without Portfolio said this thing to which I have referred. Now would he have said this thing in November 1962 or December 1962 or even January or February 1963? He would not have said it. Even though the cease-fire had come, he would not have said it in November or December 1962 or even in January or February 1963, for the simple reason that things were not still clear in the mind, it was not clear which way the things were moving. There were still very positive apprehensions of a flare-up which might have necessitated the movement of Armed Forces and other things. Today he does not come to say this thing. And I must remind the hon. Mem-

bers who spoke on the November Resolution Of 1962 that after the Colombo Proposals we passed another Resolution also. You will remember that when we passed that Resolution we passed it on the ground that it was something different from what had been stated in the Resolution passed in November.

Therefore, it is not as if we are today reviewing the situation. We are actually reviewing the situation from time to time. In the meanwhile we had actually passed two resolutions, one at the time of the invasion and another after the Colombo Proposals had been announced and which we had accepted<sup>in</sup> toto. Now the situation has developed further but in a better direction. Let us not try to deceive ourselves by thinking that it is not so. All other measures that you had taken for the emergency situation, many other measures, have been withdrawn—the restrictions on production, curb on allocation of funds to the various Ministries, etc. We get documents and letters saying that the cut that was imposed in view of the emergency has been restored. Good. It has been restored. In the production sphere, certain curbs were made in order to divert the productive energy to some other channel. These have been restored too. The other day I was reading that now the cement producers will be getting something more, which was restricted or restricted. Therefore all these things happen. By-elections are taking place in the normal way. Therefore this improvement of situation has not been in relation to the border itself. If it were not so, I would have been hard put to defend my position and to sponsor my case here. If you take the speeches of the Government leaders, you will find the same thing, not here to-day but they call press conferences and make speeches and in the speeches also they say the same thing. I think we would not be fair to ourselves if we wanted to make out as if it is the same as in November-December 1962. It is not so, TYom

our behaviour, from the various measures that we have withdrawn meanwhile in the intervening period and also because of other developments noted by us in our speeches, we have come to the conclusion that the situation has improved. I think there is no disunity in the country on this matter but why create an artificial divergence with regard to the assessment of the objective situation simply because the Government want the emergency powers to continue? Now here you say 'no fighting for some time'. It is not for some time, for sixteen months there is no fighting. That is very important, a material point in the situation. The emergency was declared not because of a mere threat but because of a grave threat as a result of external aggression, as you put it in the declaration itself. Today you cannot say, whatever may be your assessment with regard to other matters or your assessment of intentions or other things. You do not say this. Therefore I think it has to be viewed\* from that angle. After our debate last time, the Indian Express wrote an editorial and it said: "Where is the emergency"? That was the title.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE:  
That is a capitalist paper.

STOIBHUPESH GUPTA: It was\* on  
12th February:

"But there can be no two opinions that to-day, 15 months after its proclamation, the emergency lies dead on the floor and that all that it needs is a decent burial."

This is what the Indian Express wrote. Then it went on to say:

"Apart from the prevailing tension with Pakistan on the one hand, and China on the other, it cannot in all conscience be claimed by the Government that the threat to the country's security, however potential, is immediate."

[Shri Bhupesh Gupta.] The third point this paper made was:

"It is to be hoped that when the Rajya Sabha debate on the subject is resumed a fortnight hence, Home Minister Nanda will take a realistic view of the situation."

This is what was written. Other editorials have also appeared. I have got a subsequent editorial from the 'Times of India' on the President's Address which was written also after the emergency on 'Incompetence'—that was the title. They are also making fun of the proposed Eighteenth Amendment Bill and related matters connected with the emergency. Therefore other papers also wrote like that. I am not giving the quotations from the paper because it is well known in the country that the press has been reacting to it in a particular way. It shows that the volume of public opinion is against it. Do you mean to say that all of us on this question, Mr. Goenka's paper, Mr. Sahu Jain's paper and all other papers, have gone wrong? No. Understand this position. You take sometimes these publications as signs of public opinion. Therefore I say, there is no fighting today for the last 16 months. There is no fight and we should feel happy about it. Mr. Krishan Dutt was brandishing his sword but his Prime Minister is not doing it. I do not know why he is doing it. Certainly do not try to put your policy to discredit. I do not think the Prime Minister will like or even Mr Nanda will like it. Even while speaking on this subject he did not say that the danger has increased. (Interruptions). Yes. Pakistan has got in now. Then say that the Pakistani thing is there. Issue another proclamation, make another speech, start it all afresh.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: Very funny argument.

SHRI BHUPESH GUPTA: But the emergency was proclaimed to deal with a situation arising out of a certain external aggression, in certain parts of

our country. It was not because of the fact that Pakistan was receiving huge arms aid from the U.S.A. If that was so, then we should have proclaimed an emergency here as soon as the Arms Aid Agreement between Pakistan and the U.S.A. was signed in 1954. We did not do it. In fact we did not declare an emergency in the whole country even in 1948 when one-fourth or one-third of Kashmir was taken. Even to-day, between 1948 and 1962, in that period, aggression had continued there in one-third of Jammu and Kashmir embracing a population of one million people—arms had been accumulated there under the Military Pact. Everything was there which constituted a threat that way but you did not declare a state of emergency. In fact we did not discuss this matter at all from the point of view of proclamation of emergency in the House. The whole thing was felt necessary because of the development in 1962 October-November. Let us see whether from that angle it is there or whether the situation has changed for the better. It has changed for the better, there is no doubt about it. Everybody says that the emergency now remains in force only for use of the D.I.K. against the Opposition or some such thing. Therefore I cannot agree. Is this the assessment of political leadership of the country, of the Government that they are expecting an immediate attack, a resumption of military operations? No, it is not so. Then the picture would have been different, then the picture would have entirely changed, the attitude would have been different and many things would have been done. Therefore you are not even making that assessment. Whatever you may say here to score a debating point, your assessment of the situation is, whether you are right or wrong is a different matter, that the situation has improved from the point of view of the immediate threat of resumption of armed aggression.

Therefore I say that is not right. Here Mr. Nanda gave so many things about lands and all that. Now you see

what he says. It is used for military acquisition and requisitioning of lands but actually they are derequisitioning lands which they took on the declaration of the emergency. They are passing orders derequisitioning them. We know this. Therefore you cannot blow hot and cold. If we say that for the acquiring of land for firing practice we need the emergency powers, people will laugh at us as if in England, France and other countries people do not have artillery or firing practice at all. They do not have their children shooting air-guns in their backyards. They too have artillery guns as we have and they do practise but they do not need emergency powers for that. These are, therefore, lame excuses. The only excuse is this that the Congress Party and the Government need the emergency in order to persecute the people, whatever they may say here. Here I was pointing out Prof. Lal's 'Gur Satyagraha'. He was bringing some gur to Delhi. He was apprehended under the D.I.R. and put in jail. Which border was he threatening? I must know it from the Government.

SHRI A. B. VAJPAYEE: U.P.- Delhi border.

SHRI BHUPESH GUPTA: U.P. Delhi border was threatened by Prof. Lal carrying half a seer of gur? There should be a limit to a ridiculous approach to public affairs. This is what I say. Now anybody you may find whom you want to arrest for the defence of the country under the D.T.R.

Now, this is all absolutely wrong. Actually, they have no case. Emergency means more power for the bureaucracy, emergency means more power for the Ministers, emergency means more power to issue threats to the democratic rights and liberties of the people, emergency means a sword in the hands of the ruling party to brandish over the heads of the Opposition parties and emergency means that when the elections take place you can not tell the people that if they

voted against you, then the Defence of India Rules would be used as has been done in some parts of the country. This is called emergency. Have you taken emergency powers for increasing production? Have you used it for controlling prices? On every count you have failed. You should not only revoke this emergency but should pay compensation to the country for having misused power and having failed in this manner. That is what I say. There should be some sense of proportion. We do not need all these things for increasing agricultural production, which has gone down like anything—Everything has gone down. Almost all the commodities have shown a decline in production. You could not compel them to improve the production; you could not use the emergency powers to compel the employers to discharge their responsibilities. You have miserably failed in that sphere but when it came to the workers and the legitimate demands and rights of the workers, you had used these powers.

Madam Deputy Chairman, some people have said that I speak because some of our people are in jail. Naturally I am much concerned about it. Even today we have got fourteen of our comrades in jail in Maharashtra including Com. Ranadive, a member of the Central Council, Mr. Parulekar, another member of the National Council and Mrs. Parulekar who is a veteran woman worker of Maharashtra. They are all in jail and three times they were released because the orders were found not to be valid but everytime they were released, instead of releasing them. Government had them rearrested by what they called removal of the technical error. The High Court says that their detention is illegal but again the State Government passes the same order. Now, is that the way to treat the people? Having failed in this, they are doing something more. In Uttar Pradesh, six people are in detention; in Bengal there are two people in detention, belonging to our Party, and in

[Shri Bhupesh Gupta.] Tripura twenty-nine people, the entire opposition, is in jail. I have got a telegram here which says that the two M.Ps, from Tripura lodged in Hazaribagh jail are on hungerstrike. They were here at that time and within four days of their reaching their place, they were arrested. I should like the Government to prove anything against them but they have nothing. The entire opposition is in jail; who is, I would like to know, threatening Tripura at the moment. Tripura is threatened by something else, some intrusion there by the Pakistani armed forces. Are you arresting them for that also? I should like to know this. Are our comrades in Tripura in prison because something has developed between Pakistan and India? Then, say so. Our only crime was that in the Third General Elections, we captured both the Lok Sabha Seats from Tripura forming fiftyone per cent, of the votes, the majority of the votes, and In the Assembly we have just the same number. All the leaders of Tripura are in jail today.

This is not the only ground on which I demand revocation of emergency even though that in itself would be an important enough reason. I am glad Mr. Arjun Arora and Tariq supported the release of the detenus. Emergency, I say, should be revoked for the sake of democracy, for the sake of constitutional principles, for the sake of goodness in human life, for public morality. I think that if they believe in continuing this kind of thing and develop a habit of emergency, there will be less and less of difference between us and the dictatorial regimes, militarist regimes which we condemn, and we shall be more or less, acclimatised as Mr. Hare Krishna Mahlab said in the other House, to a regime of negation of democracy. Therefore, I plead with this House that this emergency should be ended. There is no need for it from the point of view of the country and certainly it needs to be revoked! from the point of view of the

country, democracy and our public life.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"This House is of opinion that having regard to the improved situation in the country the state of emergency should now be ended."

*The motion was negatived.*

#### RESOLUTION RE APPOINTMENT OF A COMMISSION ON AGRICULTURE

SHRI N. SRI RAMA REDDY (Mysore) :  
Madam, with your permission, I would like to move the following Resolution:

"This House is of opinion that Government should appoint a Commission on Agriculture (on the pattern of the Royal Commission on Agriculture of 1926-28) consisting of members representing both Houses of Parliament and experts on agriculture to enquire into the problems of agricultural research, agricultural development and agricultural education in the country, with particular reference to soils, implements, manures, seeds, irrigation, pesticides, improvement of cattle for more milk, sheep, poultry and other economic livestock, and to report on the ways and means of catching up with the progress of other advanced countries, especially in the matter of agricultural productivity."

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. GOVINDA REDDY) in the Chair"]

Mr. Vice-Chairman, it is well known that agriculture is the premier industry of India. Nearly seventy or eighty per cent, of the people are following the agricultural occupation and more than eighty to eighty-five per cent, of the people are depending directly or indirectly upon agriculture. Therefore, if agriculture shows any setback in its development, in its growth, then that will be the greatest tragedy of this country. Therefore, It